



Jannat Zubair's Pink Era is...

## SHARE

सेंसेक्स : 81,273.75  
निफ्टी : 24,876.95

## SARAFI

सोना : 9,440  
चांदी : 127.00

(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)

## BRIEF NEWS

शिक्षा विभाग को सीएम हेमंत ने अपने पास रखा

**RANCHI :** मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखा है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद लिया है। कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता (समन्वय) विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता (समन्वय) विभाग की छह दिसेंबर 2024 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले से सौंपे गए विभागों के अलावा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग आवंटित किया गया है।

ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार, आज होगी समीक्षा

**RANCHI :** झारखंड में नगर निकाय चुनाव के आसार दिखने लगे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के कंफाइल की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रिपोर्ट को कंफाइल करने की जिम्मेवारी संत जेवियर्स कॉलेज को सौंपी गई थी। आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह ने बताया कि संत जेवियर्स कॉलेज की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी समीक्षा के लिए 19 अगस्त को बैठक होगी। समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

ईसीआई से पूरा देश मांगोगा हलफनामा : राहुल गांधी

**PATNA :** वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ 'वोटर अधिकार यात्रा' के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा। गयाजी के डबूर में काफिला लंच के लिए रुका। खाने की थाली में रोटी, चावल, दाल, मिक्स वेज और पनीर की सब्जी जैसे कई व्यंजन थे, लेकिन राहुल गांधी ने बैंगन की भुजिया और लिट्टी खाई। खाने के बाद करीब एक घंटे तक उन्होंने कैंप में आराम किया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग से पूरा देश हलफनामा मांगोगा।

लोकसभा में शुभांशु शुक्ला पर हुई विशेष चर्चा

**NEW DELHI :** सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में दोपहर 2 बजे भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश शुभांशु के लौटने पर सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और चर्चा को तैयार नहीं है। मंत्री ने कहा कि आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, एस्ट्रोनॉट से कैसे हो सकती है। शुभांशु एयरफोर्स के सिपाही हैं, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं है।

# भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने नियुक्ति को दी थी चुनौती डीजीपी अनुराग गुप्ता को 'सुप्रीम' राहत, मरांडी की याचिका खारिज

PHOTON NEWS RANCHI :

सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजूरिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुराग गुप्ता को सभी नियमों का पालन करते हुए डीजीपी बनाया गया है। अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।

**बाबूलाल मरांडी ने उठाए थे सवाल :** बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति

सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजूरिया की पीठ में हुई सुनवाई



सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सरकार का रखा पक्ष, नियमों का दिया हवाला

नियुक्ति पर केंद्र और राज्य आमने-सामने

डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले थे। राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र भेजा, लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

को चुनौती दी थी। याचिका में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया

## राजनीतिक बदला लेने के लिए न किया जाए कंटैक्ट और पीआईएल का इस्तेमाल : SC

इस मामले की सुनवाई के दौरान राजनीतिक विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय की अवमानना के अधिकार क्षेत्र और जनहित याचिकाओं के इस्तेमाल पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है। सीजेआई की अध्यक्षता में गठित पीठ ने कहा कि राजनीतिक विवादों का निपटारा मतदाताओं के सामने होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ अनुराग गुप्ता को राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि झारखंड के मामले में, हम नहीं चाहते कि अवमानना के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जाए। कोर्ट ने कहा, अगर आपको किसी विशेष नियुक्ति से कोई समस्या है, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाएं। लेकिन अपना राजनीतिक बदला मतदाताओं के सामने लें।

गया था। मरांडी का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में

किसी विशेष नियुक्ति से कोई समस्या है, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाएं



बाद में विस्तार से की जाएगी हियरिंग

न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने सुझाव का समर्थन किया कि पुलिस प्रमुख की नियुक्ति यूपीएससी के बजाय मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। प्रकाश सिंह ने न्यायालय को बताया कि राज्य डीजीपी नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को दरकिनार करने के लिए एडीजीपी की नियुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा

कि ये सभी मामले इसलिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि न्यायालय की निगरानी बंद हो गई है। रामचंद्रन ने सुझाव दिया कि शीर्ष न्यायालय के फैसले का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट की विशेष पीठें हर तीन महीने में बैठक कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि राज्यपालों की शक्तियों पर सविधान पीठ के मामले के बाद इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीएससी पैनेल से

चुने गए डीजीपी को हटाकर अनुराग गुप्ता को गलत तरीके से नियुक्त किया गया।

## बालिका आवासीय स्कूल के हॉस्टल में लग गई आग हॉल नंबर 5 जलकर खाक



PHOTON NEWS LATEHAR :

सोमवार को सुबह लातेहार जिले के बारियातु प्रखंड स्थित बालिका आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में अचानक आग लग गई। यह घटना सुबह छह से साढ़े छह बजे के बीच की है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग हॉस्टल के हॉल नंबर-5 में तेजी से फैल गई। वहां रखे सभी बेड, गद्दे, बैग और छात्राओं के निजी सामान जलकर राख हो गए। संयोग से घटना के समय सभी छात्राएं मैदान में फरेड और पीटी कर रही थीं, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। थाना प्रभारी रंजन पासवान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा

टला बड़ा हादसा

लातेहार की घटना, हादसे के दौरान पीटी के लिए मैदान में गई थी छात्राएं, बेड और सामान जले

229 नामांकित छात्राओं में 200 इस हॉस्टल में रहकर करती हैं पढ़ाई

कि इस घटना में कोई भी छात्रा घायल नहीं हुई है, यह राहत की बात है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्राओं को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।

हर कमरे में रहती हैं 40 छात्राएं

आग लगने के दौरान हॉस्टल परिसर में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन, गार्ड अफिफ उरांव ने साहस दिखाते हुए छात्राओं के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर बारियातु थाना प्रभारी रंजन पासवान दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्राओं को

सुरक्षित स्थान पर भेजा। इसके बाद सुबह करीब साढ़े नौ बजे अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग को पूरी तरह से बुझाया गया। तब तक हॉस्टल का एक बड़ा हिस्सा आग से क्षतिग्रस्त हो चुका था। विद्यालय में कुल 229 छात्राएं नामांकित हैं। इनमें से लगभग 200 छात्राएं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल में कुल पांच कमरे बने हैं। हर कमरे में करीब 40 छात्राएं रहती हैं।

झारखंड में परेशानी बढ़ाएगी वर्षा, आईएमडी का अलर्ट

## बारिश का दौर फिर शुरू किसानों के खिले चेहरे



PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड में एक बार फिर से बारिश परेशानी बढ़ाएगी। इसके लिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है, जो 22 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। सोमवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि, भारी बारिश से आम जन-जीवन भी प्रभावित हुआ है। झारखंड के रांची सहित विभिन्न जिलों में बारिश हुई।

● भारी वर्षापात से आम जन-जीवन भी प्रभावित, कहीं रुक-रुक कर, तो कहीं लगातार बारसता रहा गातार

● 22 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान

हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मानते रिस्स निदेशक विभाग ने ठहराया दोषी

**RANCHI :** रिस्स के निदेशक डॉ. राजकुमार पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी ठहराया है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार रिस्स निदेशक को तुरंत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना था। साथ ही दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करते हुए विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध करवानी था, लेकिन निदेशक ने रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। इस मामले में विभाग ने निदेशक को लगातार चौथा रिमाइंडर भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस मामले में निदेशक को पहले ही तीन रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब चौथी बार निदेशक को पत्र भेजा गया है। दोषी अधिकारियों की पहचान नहीं हो पाई और भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम सांजनिक्त नहीं किए गए। कार्रवाई रिपोर्ट का अभाव। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का कोई ब्यौरा विभाग को नहीं दिया गया। न्यायालय की अवमानना एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है।

### ! श्रद्धांजलि !

गरीब छात्रों के भाग्य विधाता, ज्ञान का दिव्य प्रकाश जलाता, मौन रहकर समस्याओं से जूझता, कठिन से कठिन क्षण में भी हठ पल पल बनकर खड़ा रहता, कुड़मालि एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का संवार हेतु हमेशा तत्पर रहता। समाज को एक दिशा दिखाता, वहीं थे हमारे 'चड़े सार'।

**परम आदरणीय श्याम सुंदर महतो जी**

वाहे छात्र हो या शिक्षक हो या समाज, उनसे मिलते ही लोग अपनापन का एहसास करने लगते थे। पता नहीं वह दिन कब आया कि उनके गुण से परिपूर्ण कोई व्यक्ति इस दुनिया में फिर से जन्म लेगा। मधुसूदन विद्यालय के संस्थापक, समाज के एक प्रेरणा स्रोत, उनके किए गए कार्यों का दीप हमेशा जलता रहे और हमारा मार्गदर्शन करता रहे, यही हम सब की कामना है एवं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

**मधुसूदन परिवार, झारखंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद, कला संस्कृति विकास केंद्र द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित।**

उनके स्मृति में निम्न कार्यक्रम मधुसूदन स्कूल परिसर, आसनतलिया, चक्रधरपुर में आयोजित की जा रही है

दिनांक 19 अगस्त 2025 : दशकर्म  
दिनांक 20 अगस्त 2025 : कुटुंब भोज एवं मित्र भोज, रामय - अपराह्न 02 बजे से।

**निवेदक - बलराज हिंदवार (पुत्र)**

Your Degree, Your Way

UGC Recognized

# 100% ONLINE

MBA | MCA  
BBA | BCA  
B. COM

KEY BENEFITS

Flexible Learning | Affordable Fee | Global Recognition | Industry-Relevant Curriculum  
Experienced Faculty Members | Interactive Learning | Student Support Services | Career Opportunities

AS PER UGC | Pursue Two Programs Simultaneously (One Regular & One OL or Two OLs)  
OL Program Degree is equivalent to Conventional Program Degree

AVAIL EASY EMI FEE PAYMENT OPTIONS WITH

ENROLL TODAY **7370-01-7370** VISIT WEBSITE **onlineaju.ac.in**

**BRIEF NEWS**

**कैदी की रिमस ले जाने के दौरान हुई मौत**  
**RAMGARH :** रामगढ़ उपकारा में बंद कैदी जयमंगल हाजरा की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि वह घनबाद जेल में था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे वर्ष 2024 में रामगढ़ उपकारा में शिफ्ट किया गया था। जयमंगल कुछ दिनों से बीमार था। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सोमवार को सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया। वहां से उसकी बिगड़ी हालत को देख चिकित्सकों ने उसे रांची स्थित रिमस रेफर कर दिया। लेकिन, उसने रिमस ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

**गहरे तालाब में डूबकर किशोर की मौत**

**BOKARO :** बालीडीह थाना क्षेत्र के नरकरा गांव में सोमवार की सुबह उस वक्त मातम छा गया, जब गहरे तालाब से 14 वर्षीय सिंदू कुमार का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, सिंदू रविवार की दोपहर अपने दो दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और फिसलकर गहरे पानी में चला गया। साथी बच्चे डर गए उन लोगों ने किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। रविवार की देर रात तक परिजन और ग्रामीण उसकी खोज करते रहे, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने तालाब के समीप शव को देखा और इसके सूचना पुलिस व परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन, मुखिया बबीता देवी, पंचायत समिति सदस्य रीना एकका तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव की पहचान की। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

**कोडरमा घाटी में दो ट्रकों की टक्कर, तीन घायल**



**KODERMA :** कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची-पटना मुख्य मार्ग एनएच-20 पर स्थित कोडरमा घाटी के नौवें माइल के पास सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दोनों ट्रकों के चालक और एक उपचालक शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चावल लदा एक ट्रक कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से होते हुए कोडरमा मार्ग से बिहार की ओर जा रहा था। उसी समय विपरीत दिशा से ईट लदा एक ट्रक आ रहा था। नौवें माइल के समीप दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई, जिससे चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दौरान पीछे से आ रहा एक ट्रैक्टर भी ईट लदे ट्रक से टकरा गया, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रक में रखा सारा चावल सड़क पर बिखर गया। दुर्घटना में चावल लदे ट्रक का चालक व उपचालक तथा ईट लदे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान बिहार निवासी अखर शोख (पिता- मो. नाजिर शोख), छट्टू यादव (पिता- रामबृक्ष यादव) और हजारीबाग निवासी अरुण मेहता (पिता- अयोध्या मेहता) के रूप में हुई है। हादसे के कारण कोडरमा घाटी में दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे घंटों तक जाग की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए क्रेन मंत्रावाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन की तत्परता से धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका।

**मुआवजा व रोजगार की मांग पर उग्र प्रदर्शन, ट्रांसपोर्टिंग टप**

**PHOTON NEWS HAZARIBAG :** कट ऑफ डेट, मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर सोमवार को युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रैयतों और ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। बड़कागांव के 13 माइल समेत कई स्थानों पर ग्रामीणों ने कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग रोक दी। इतना ही नहीं, कंपनियों में काम करने जा रहे कर्मचारियों को भी रोक कर उन्हें पैदल जाने पर मजबूर कर दिया। अचानक हुए आंदोलन से माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और रैयत जुट गए। दूसरी ओर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। हजारीबाग के एसडीएम, एसडीपीओ,



प्रदर्शन करती महिलाएँ व अन्य

बड़कागांव थाना के अंचल निरीक्षक और बड़कागांव बीडीओ के नेतृत्व में प्रशासन ने मोर्चा संभाला। दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी का माहौल रहा, लेकिन अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियां लगातार उनकी उपेक्षा

**कुख्यात डबलू सिंह ने पलामू पुलिस के सामने कर दिया आत्मसमर्पण**

**झारखंड का पहला गैंग लीडर, जिसने पुलिस के समक्ष डाले हथियार**

**PHOTON NEWS PALAMU :** पलामू में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम गौतम कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह आखिरकार पुलिस के सामने झुक गया। कुख्यात गिरोह के सरगना डबलू सिंह ने रविवार की रात लगभग 10.30 बजे शहर थाना में पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड में यह पहला मौका है जब किसी सक्रिय गैंग के सरगना ने औपचारिक तौर पर पुलिस के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने की घोषणा की है। डबलू सिंह मूल रूप से लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के फुलांग गांव का रहने वाला है। वह वर्ष 2005 से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा।



पत्रकारों को मामले की जानकारी देती एसपी रीष्मा रमेशन

**कुणाल सिंह हत्याकांड के बाद हुआ था फरार**

वर्ष 2014 में लातेहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और वह लंबे समय तक देवघर जेल में रहा। 2018 में बेल पर बाहर आने के बाद उसने फिर से सक्रियता बढ़ाई। 3 जून 2020 को शहर थाना क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या हुई। इस हत्याकांड में डबलू सिंह गिरोह का नाम सामने आया और तभी से वह फरार चल रहा था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 37 अपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण उसका नेटवर्क पलामू, गढ़वा, और रंगदारी भी शामिल हैं। लातेहार, चतरा, हजारीबाग,

**मुख्यधारा में शामिल होने की ओर कदम**

आत्मसमर्पण के बाद डबलू सिंह ने कहा कि उसने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति और पलामू एसपी की पहल से यह निर्णय लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उसने कहा - मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ, थोड़ी-बहुत गलती हुई है। कोर्ट का जो आदेश होगा, उसका पालन करूंगा। अपने साथियों से अपील करता हूँ कि वे अपराध छोड़कर सही रास्ते पर लौटें।

रामगढ़, रांची और जमशेदपुर तक फैला हुआ था।

एसपी रीष्मा रमेशन ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि डबलू सिंह सात साल से फरार था। 2005 से 2014 तक उसके खिलाफ 33 मामले दर्ज हुए थे, जबकि जेल से बाहर आने के बाद भी उस पर चार मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर नक्सली आत्मसमर्पण करते रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला है जब किसी बड़े अपराधी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। यह पलामू पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस कार्रवाई में शहर थाना के तत्कालीन प्रभारी देवधर पोद्दार और उनकी टीम के प्रयास की सराहना भी की।

**बोकारो में 80 किलो गांजा व भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, दो गिरफ्तार**

**गोमिया थाना के सियारी गांव में की गई छापेमारी, मौके से भाग गया मकान मालिक**

**PHOTON NEWS BOKARO :** बेरमो अनुमंडल पुलिस ने रविवार को देर रात छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा और अवैध शराब बरामद की है। बेरमो एसडीपीओ बशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि जरीडीह थाना क्षेत्र के कारोबारी सोनू कुमार राय की निशानदेही पर गोमिया थाना क्षेत्र के सियारी में कार्रवाई की गई, जहां से 80 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर बेरमो एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित छापेमारी टोल ने गांधीग्राम सियारी बिल्डा टोलों के पास सुजीत कुमार साव के मकान में छाप मारा और गांजा व



जब्त किया गया गांजा व अवैध शराब

शराब बरामद की। हालांकि मकान मालिक सह कारोबारी सुजीत कुमार साव अंधेरे में भागने में सफल रहा। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक उत्पादों और उसके कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी

की जा रही है। इसी क्रम में रविवार देर रात को जरीडीह थाना क्षेत्र के एक कारोबारी के यहां छापेमारी की गई। गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ में उसने गोमिया थाना क्षेत्र के सियारी बिल्डाटोल निवासी सुजीत कुमार

साव का नाम बताया। कहा कि वहीं से बड़ी मात्रा में गांजा की सफाई अन्य थाना क्षेत्रों व दुकानों में की जाती है। निशानदेही के आधार पर जरीडीह व पेटरवार थाना पुलिस की मदद से छापेमारी की, जहां से एक-एक किलोग्राम के गांजा के बंडल 80 पीस जिसका कुल वजन 80 किलो है सहित बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ के अलावा जरीडीह थाना प्रभारी बिपिन महतो, पेटरवार थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार मेहता सदलबल मौजूद थे।

**लातेहार में जेजेएमपी के दो उग्रवादी गिरफ्तार**



पत्रकारों को मामले की जानकारी देते डीएसपी अरविंद कुमार

**LATEHAR :** पुलिस ने छापेमारी अभियान चला कर सदर थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ गांव के पास से झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार थाना क्षेत्र के नवागढ़ गांव निवासी अमीन अंसारी और नरेशगढ़ गांव निवासी कृष्णा साहू शामिल हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के दो सदस्य सदर थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ गांव के पास देखे गए हैं। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम गठित की गई और उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। पुलिस को देखकर दोनों उग्रवादियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि पूर्व में भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। परंतु उस दौरान दोनों उग्रवादी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे।

**एसडीपीओ कार्यालय के पास निकाला जा रहा था कोयला, हो रही थी तस्करी, मोदीडीह कोलियरी क्षेत्र में 10 परिवार प्रभावित**

**अवैध कोयला उत्खनन से सिजुआ में हो गया भू-धंसान, दहशत में लोग**

**PHOTON NEWS DHANBAD :** घनबाद जिले के कतरास कोयलांचल में अवैध कोयला उत्खनन का काला धंधा अब पूरी तरह से बेखुफ हो चुका है। सोमवार की सुबह सिजुआ क्षेत्र में अवैध उत्खनन के कारण भू-धंसान हो गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं, बाघमारा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) के कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर प्रशासन की निष्क्रियता और माफिया के दुस्साहस को उजागर कर दिया है। 2006 में भी गिरा था घर, फिर वहीं मंजर देखा : जोगता थाना क्षेत्र के मोदीडीह कोलियरी अंतर्गत नया श्यामबाजार की शबरी बस्ती में सोमवार तड़के करीब तीन बजे जोरदार आवाज के साथ भू-धंसान



भू-धंसान से क्षतिग्रस्त मकान

**सरकार का नुमाइंदा बताकर लोगों को डराते थे तस्करी**

हुआ। यह भू-धंसान अवैध खनन के कारण जमीन के खोखला होने से हुआ। इस घटना में दो घरों के साथ-साथ आसपास की जमीन में भी गहरी दरारें पड़ गईं, जिससे

**कतरास में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कारोबार**

एक तरफ जहां सिजुआ के लोग भू-धंसान से सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बाघमारा अनुमंडल में अवैध खनन का काम बेरोकटोक जारी है। पिछले दिनों बाघमारा के केशरगढ़ स्थित जमुनिया नदी के पास हुए चाल घंसेने की दुखद घटना की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अवैध कोयला कारोबारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। अंगारपथरा औपी क्षेत्र के कांटा पहाड़ी के पास अवैध मुहाना बनाकर खनन धड़ल्ले से जारी है। यह इलाका एसडीपीओ कार्यालय से बहुत करीब है, फिर भी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। यहां सैकड़ों मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में यह अवैध खनन चल रहा है, वह मा अम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी का है। एक ओर जहां कंपनी को कोयले की निकासी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ये अवैध कारोबारी बेधड़क अपना काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मा अम्बे आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल भी इस अवैध गतिविधि पर मुदरशक बनी हुई है। इस अवैध कारोबार का मुख्य सरगना लालू बताया जा रहा है, जबकि अनूप, बुनूर, भोलू और प्रिस जैसे नाम भी इस गोरखधंधे में शामिल हैं।

मौकसे वाली बात यह है कि एसडीपीओ कार्यालय के ठीक पास में ही, जोगता थाना क्षेत्र के बंद पड़े परियोजना चालीस नंबर में कई अवैध खनन और अवैध कोयला डिपो भी संचालित हैं। भले ही यह क्षेत्र घनबाद डीएसपी के अधीन आता हो, लेकिन एसडीपीओ कार्यालय के इतने करीब इनका संचालन गंभीर सवाल खड़े करता है। इन डिपो का संचालन पप्पू और सन्नी कर रहे हैं। ये लोग खुद को सरकार का नुमाइंदा बताकर बेखुफ और बेरोकटोक कोयले की अवैध तस्करी कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है।

बताया कि जब अजायब आई, तो ऐसा जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई। लौ में परिवार के साथ किसी तरह बाहर भागा। मेरा घर तो 2006 में भी गिरा था और अब फिर वहीं

**ग्रामीणों ने कहा- जान और माल दोनों खतरे में**

इस तरह की घटनाएं न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि यह पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। अनियंत्रित खोदने से भूस्खलन और जमीन धंसने का खतरा बढ़ता है। जमुनिया नदी के पास हुए हादसे ने पहले ही कई जिंदगियां छीन ली हैं, फिर भी प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी अवैध गतिविधि कैसे चल रही है। क्या यह मिलीभगत का नतीजा है? स्थानीय ग्रामीण कुलाश का कहना है कि इस पूरे मामले पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि अवैध कोयला माफिया के इस दुस्साहस को रोक जा सके और निंदीय मजदूरों की जान को बचाया जा सके। एक अन्य ग्रामीण, दिलीप कुमार ने बताया कि उनका घर इसी अवैध खनन स्थल के पास है और उनके घरों के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है, जिससे उनके घरों के जमीनीपत होने की संभावना है। दिलीप कुमार ने कहा कि प्रशासन को न केवल अवैध मुहानों को बंद करना चाहिए, बल्कि इसमें संलिप्त बड़े वेहरो और पुलिस-प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय ग्रामीण सविता देवी कहती हैं कि जब तक इस संगठित अपराध पर लगाम नहीं लगाई जाती, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और गरीबों की जान जाती रहेगी।

**ग्रामीणों ने कहा- जान और माल दोनों खतरे में**

यह घर बनाया था और एक झटके में सब मिट्टी में मिल गया। हमें ऐसे डर के साथ में जाना पड़ेगा। इसी तरह, गोविंद भुइयों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हमने अपनी सारी जमा-पूजी लगाकर

मंजर आज देखें। हमें कब तक ऐसे डर के साथ में जाना पड़ेगा। इसी तरह, गोविंद भुइयों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हमने अपनी सारी जमा-पूजी लगाकर



**घनबाद जेल में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास**

**DHANBAD :** नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, लेकर भागने और लड़की को गर्भवती करके के मामले में 22 साल की सजा काट रहे जितेंद्र रवानी नामक कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। इस घटना को अंजाम देने से पहले कैदी ने अपने हाथ की हथेली पर आई लव यू बाबू और एक संदेश भी लिखा। घटना के बाद जेल प्रशासन ने जितेंद्र को तत्काल एएसएएमएसपीएच में भर्ती कराया। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर अस्पताल में जितेंद्र के परिजन भी पहुंचे गए हैं। जितेंद्र मूल रूप से गोधर रवानी बस्ती का रहने वाला है। दो साल पूर्व वह एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने जितेंद्र के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने काफी दिनों बाद दोनों को बरामद किया था। उस वक्त लड़की चार माह की गर्भवती थी। पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद युवक को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जितेंद्र एक साल से जेल में है। जितेंद्र के परिजनों ने बताया कि रविवार की देर रात उन्हें जेल से फोन आया कि उनका बेटा अस्पताल में भर्त है। जब परिजन पहुंचे तो जानकारी मिली कि उसने जेल के अंदर आत्महत्या का प्रयास किया था। आत्महत्या से पहले जितेंद्र ने अपनी हथेली पर पेन से कुछ लिखा है, जिसमें इस घटना के लिए किशोरी को दोषी ठहराया है।

# बड़े अपराधियों के करीबियों पर एटीएस की टेढ़ी नजर, एक दर्जन को नोटिस

**PHOTON NEWS RANCHI :** झारखंड की एंटी टेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की टीम बड़े अपराधियों की काली कमाई पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस नजरिए से आधा दर्जन से अधिक कुख्यात अपराधियों की काली कमाई पर अपनी नजर गड़ा दी है। अब झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोहों की कमाई से अमीर बनने वाले और बेहिसाब संपत्ति बनाने वाले से एटीएस ने उनकी कमाई का हिसाब मांग दिया है। अपनी कमाई का हिसाब नहीं दे पाएंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अमन श्रीवास्तव, सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान, डब्लू सिंह, मयंक सिंह और विकास तिवारी जैसे गैंगस्टर्स की काली कमाई को कारोबार में लाने वाले सेफेदपोश, गैंगस्टर्स के करीबी और रिश्तेदार बड़े संकट में फंस पाए हैं।

## काली कमाई पर काररा प्रहार करने के लिए बड़े स्तर पर बनाया जा चुका है प्लान अगर समय पर हिसाब विलियर नहीं किया गया तो जब्त कर ली जाएगी संपत्ति

संगठित आपराधिक गिरोहों की मदद से अमीर बनने वालों की संपत्ति का मांगा हिसाब ऐसे लोगों की आर्थिक मजबूती को तोड़ने के लिए सक्षम हो चुकी है अन्य कई एजेंसियां



**दस से ज्यादा लोगों की हुई पहचान**  
झारखंड में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह पर लगातार एटीएस की नजर है और उनसे उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। अब उन तमाम लोगों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा, उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने जो संपत्ति बनाई है, उसमें उनके क्रिमिनल रिश्तेदार का कोई हाथ नहीं है। अगर वे इसे साबित नहीं कर पाएंगे, तो नए कानून के अनुसार उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

**कई प्रकार की संपत्तियों की मिली है जानकारी**  
झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के गतिविधियों पर ब्रेक लगाने के लिए अब सभी वैसे गैंग्स के प्रमुखों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में गैंग्स के कई तरह की संपत्तियों की जानकारी एटीएस को हासिल हुई है। हाल में ही कुख्यात अमन साहू और सुजीत सिन्हा से पूछताछ कर कई जानकारी हासिल की गई है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के कुख्यात अमन श्रीवास्तव, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और प्रिंस खान जैसे कई दुर्बत अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति का पता एटीएस को मिल चुकी है। अब धीरे धीरे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत जो संपत्तियां अपराधियों के नाम पर हैं, उसे सीधे तौर पर जब्त किया जाएगा।

**पुराने मामलों में भी की जाएगी कार्रवाई**  
नए कानून के तहत नोटिस पाने वाले व्यक्तियों को यह सबूत देना होगा कि उनकी संपत्ति वेध तरीके से अर्जित की गई है। अगर वे यह साबित नहीं कर पाते हैं तो संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। यह कानून पुलिस को बड़ी मदद देने वाला साबित होगा। एटीएस की यह कार्रवाई केवल वर्तमान अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन तमाम पुराने मामलों में भी होगी, जिनमें अपराधियों की संपत्ति अब तक सुरक्षित पड़ी है। कई अपराधियों ने अपनी अवैध कमाई को जमीन और प्रॉपर्टी में लगाया है, जिसे अब कानूनी शिकंजे में लाने की तैयारी है।

## तीन साल की हो सकती है सजा

झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों के काली कमाई का निवेश करने वाले लोगों की सूची बना कर उन्हें नोटिस किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद चाहे गैंगस्टर के परिवार वाले हो या फिर उनके नजदीकी दोस्त या फिर बिजनेसमैन, उन सबको खरीदी गई संपत्ति और किए गए निवेश को लेकर पूछता सबूत देने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो नए कानून के हिसाब से तीन साल की सजा तो है ही सारी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। एसपी ऋषभ झा के अनुसार, नए आपराधिक कानून में बीएनएस के सेक्शन 111 के सब-सेक्शन छह में यह प्रावधान है कि अगर किसी की भी द्वारा या



ऑर्गेनाइज्ड क्राइमद्वारा किसी दूसरे के नाम पर भी प्रॉपर्टी ली गई है, तो उसमें पुलिस उन्हें नोटिस देगी। जिस व्यक्ति को यह नोटिस जाएगा, उसे यह पूछ करना होगा कि उनकी संपत्ति में किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द्वारा कमाए गए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

## कोयला, बालू और खनन क्षेत्र में काली कमाई

झारखंड में संगठित अपराध का नेटवर्क कोई नया नहीं है। वहाँ से कोयला, बालू और खनन क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों ने बड़ी-बड़ी संपत्तियां खड़ी की हैं। इन अपराधियों ने अपने प्रभाव और पैसे के

दम पर स्थानीय राजनीति, कारोबार और समाज में भी पैठ बना ली है। कई बार इन अपराधियों के रिश्तेदार और सहयोगी बड़े कारोबारी या समाजसेवी के रूप में भी सामने आते हैं।

### BRIEF NEWS

**तल्हा खान को बीएनएस 479 के तहत मिली बेल**  
RANCHI : सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम के आरोपी तल्हा खान को रांची पीपल्स एक्ट (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 479 के तहत जमानत मिली है। यह धारा उन आरोपियों को जमानत का हकदार बनाती है, जिन्होंने पहली बार अपराध किया है और जिस अपराध में वे आरोपी हैं, उसमें दी जाने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा जेल में बिता चुके हैं। तल्हा खान इंडी के कांड संख्या 01/2023 में आरोपी हैं।

### बारिश के कारण मूर्तियों को सुखाने में परेशानी

RANCHI : गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा नजदीक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्ति बनाए जा रहे हैं। मूर्तिकारों को मूर्तियों को बारिश से बचाने के लिए इस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मूर्तिकार दिन-रात मेहनत कर भगवान की प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, लेकिन बारिश और तेज हवाओं ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। खुले में मूर्तियों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। प्लास्टिक से ढककर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हवा और नमी के आगे यह भी नाकाम हो रही है। बारिश के कारण मूर्तियों पर चढ़ा लेप बार-बार उखड़ जा रहा है। नमी की वजह से प्रतिमाएं सूख नहीं पा रही, जिससे उन पर रंग चढ़ाना लगभग मुश्किल हो गया है।

## आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने कांके के अंचलाधिकारी से की मुलाकात



**PHOTON NEWS RANCHI :** सोमवार को कांके प्रखंड आजसू कमेटी के अध्यक्ष अमन लाल शाहदेव के नेतृत्व में आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने कांके अंचलाधिकारी अमित भगत से औपचारिक भेंट की। इस दौरान अंचलाधिकारी का बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। साथ ही कांके क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रही जमीनों की जमाबंदी,

दाखिल खारिज और जमीन ऑनलाइन से संबंधित समस्याओं पर भी अंचलाधिकारी से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में आजसू के जिलाध्यक्ष संजय महतो, महिला जिलाध्यक्ष वीणा देवी, जिला उपाध्यक्ष मोजीबुल अंसारी, अमन लाल शाहदेव, वीरेंद्र तिवारी, एतवा उरांव, सूरज मिश्रा, सुरेंद्र महतो, परसनाथ महतो, हरिश्चंकर महतो, मनोज महतो मौजूद थे।

## खाद्य आपूर्ति प्रबंधन में सुधार की सीएस ने की समीक्षा, अधिकारियों से कहा- कोई योग्य लाभुक न रहे वंचित नए लाभुकों को योजना से जोड़ें

# कोई योग्य लाभुक न रहे वंचित नए लाभुकों को योजना से जोड़ें

### हर माह करें भौतिक निरीक्षण, रिकॉर्ड और बुक कीपिंग रखें अप-टू-डेट



**PHOTON NEWS RANCHI :** सोमवार को मुख्य सचिव (सीएस) अलका तिवारी ने राज्य के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुकों को चिह्नित कर प्राथमिकता के स्तर पर उनका नाम हटाएं, ताकि नए लाभुक जोड़े जा सकें। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस बात पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे। लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों। इसमें कोई समस्या हो तो उसका परीक्षण करें कि कहां दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग अप-टू-डेट रखें। मौके पर खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जागरूकता पर मुख्य सचिव ने दिया बल

मृत लाभुकों को चिह्नित कर प्राथमिकता के स्तर पर उनका नाम हटाएं

प्रक्रिया में इस बात पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे

### साल में दो बार हो धोती-साड़ी का वितरण

मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इस काम में तेजी लाएं। उन्होंने इसके लिए उड़नदस्ता टीम बना कर वितरण की जांच करने का भी निर्देश दिया, जिससे यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं है। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के

### गोदामों के लिए एक्शन प्लान

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी इसे कार्यशील बनाया जा सकता है। समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण

कई गोदाम उपयोग में नहीं हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से इसमें रुचि लेकर गोदामों को उपयोगी बनाया सुनिश्चित कराएं। इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई।

कई गोदाम उपयोग में नहीं हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से इसमें रुचि लेकर गोदामों को उपयोगी बनाया सुनिश्चित कराएं। इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई।

## रिस्स डेंटल इंस्टीट्यूट ने लगाया ओरल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर एक्सपर्ट्स ने कई मरीजों को दी सलाह हेल्थ कैम्प में की गई 105 लोगों की जांच

**PHOTON NEWS RANCHI :** रिस्स के डेंटल इंस्टीट्यूट के ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग द्वारा इंडियन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के तत्वावधान में 18 और 19 अगस्त को दो दिवसीय ओरल कैंसर स्क्रीनिंग और तंबाकू नियंत्रण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्देश्य लोगों में ओरल कैंसर की समय रहते पहचान और तंबाकू की लत से जुड़ी बीमारियों को रोकना है। इस कड़ी में 18 अगस्त को शिविर सामुदायिक



स्वास्थ्य केंद्र कांके, आयुषान आरोग्य मंदिर बोड्डेया और दुबलिया में आयोजित किया गया। जहां लगभग 105 लोगों की जांच की गई। स्क्रीनिंग के दौरान जिन मरीजों में ओरल ल्यूकोप्लाकिया, ओरल स्वाम्यूकस फायब्रोसिस और

टोबैको पाउच केराटोसिस जैसे कैंसर पूर्व लक्षण पाए गए। उनकी जांच टोल्युडीन ब्लू स्टेनिंग और ओरल स्मॉयर टेस्ट से की गई। तंबाकू सेवन करने वाले मरीजों की जांच कोटिनिन डिटेक्शन किट के माध्यम से की गई।

## रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर निगम सख्त प्रशासक ने दिए कड़े निर्देश



**RANCHI :** रांची नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ, सुगम यातायात युक्त के साथ अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से निगम की इनफोर्मेसट शाखा द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में इनफोर्मेसट टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। प्रशासक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों एवं सभी कॉन्वेंटिंग सड़कों से अतिक्रमण को हटाने हेतु सख्त अभियान चलाया जाए। उन्होंने प्रत्येक जॉन में नियमित माइकिंग कर लोगों को स्वच्छ से अतिक्रमण हटाने को प्रेरित करने और चेतावनी के बावजूद न हटाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि पुराना नुक़्त की स्थिति में अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मेन रोड, कांके रोड, लालपुर, सकूलर रोड, डोरंडा और बायपास रोड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निगम की भूमि, पार्क, बस स्टैंड और वाहन पड़ाव जैसे स्थलों से भी सभी अवैध वेंडरों को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी। अभियान के बाद दोबारा अतिक्रमण की स्थिति पर संबंधित इनफोर्मेसट टीम को उत्तरदायी माना जाएगा। भवन निर्माण सामग्री के कारण मार्ग जाम की स्थिति में तत्काल कार्रवाई को का निर्देश दिया गया। वहीं कोटापा एक्ट और सिगल पूजना व्हाट्सएप पर सख्ती, अवैध दुकानों और संरचनाओं के विच्छेद भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

## डायल 112 पब्लिक की शिकायत पर अब 12.47 मिनट में पहुंचने लगी है सहायता

# धीरे-धीरे पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में आ रहा सुधार

**PHOTON NEWS RANCHI :** झारखंड पुलिस की कार्यशाली और सिस्टम में धीरे-धीरे सुधार के बेहतर लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी डायल 112 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब राज्य में किसी भी नागरिक की आपातकालीन शिकायत पर पुलिस की टीम औसतन 12 मिनट 47 सेकंड में मौके पर पहुंच रही है। यह समय पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और यह संकेत देता है कि आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में झारखंड पुलिस लगातार प्रयासरत है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बीते एक महीने में इस सिस्टम के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि हर दिन औसतन 467 कॉल डायल 112 पर प्राप्त हो रही हैं। इन कॉल में छोटी-बड़ी सभी तरह की आपात स्थितियां शामिल होती हैं, जैसे- सड़क दुर्घटनाएं, झगड़े, चोरी, महिलाओं से संबंधित अपराध, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य किसी भी प्रकार की मदद।

## आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास जारी रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के पास आ रहे हर दिन औसतन 467 कॉल

जुलाई में सेंट्रल डेस्क को राज्यभर से प्राप्त हुई 14 हजार से अधिक शिकायतें तकनीकी साधनों के इस्तेमाल से बड़ी पुलिस की कार्यक्षमता और पारदर्शिता

**जिलों के हिसाब से रिस्पांस टाइम**  
रिपोर्ट में जिलावार औसत रिस्पांस टाइम का भी विश्लेषण किया गया। इसमें स्पष्ट हुआ कि कुछ जिलों में पुलिस बेहद तेजी से घटनास्थल तक पहुंच रही है, जबकि कुछ जिलों में यह समय अपेक्षाकृत अधिक है। बोकारो में औसतन 10.21 मिनट में पुलिस मदद पहुंच रही है। धनबाद का समय 11.33 मिनट, देवघर 11.40 मिनट, हजारीबाग 11.42 मिनट और गुमला 11.42 मिनट दर्ज किया गया है। ये जिले औसतन समय से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खूंटी जिले में यह समय 17.19 मिनट, चाईबासा में 16.37 मिनट और लातेहार में 16.21 मिनट है, जो औसत से काफी अधिक है। दुमका में 15.12 मिनट, साहेबगंज में 15.40 मिनट और सिमडेगा में 14.56 मिनट का समय दर्ज किया गया। इसके अलावा गढ़वा और रामगढ़ में औसतन 12.53 मिनट, गिरिडीह में 13.09 मिनट, लोहरदगा में 13.23 मिनट और पलामू में 13.47 मिनट का समय सामने आया। गोड्डा (14.19 मिनट), पाकुड़ (14.04 मिनट) और पलामू (14.04 मिनट) जैसे जिलों में भी औसतन समय थोड़ा अधिक है।



**740 मामलों को मैनुअल प्रक्रिया से निपटारा**  
रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने राज्यभर से कुल 14,014 शिकायतें सेंट्रल डेस्क को प्राप्त हुईं। इनमें से 13,274 शिकायतों को मोबाइल डेटा टर्मिनल (एसडीटी) टैब के माध्यम से निपटारा गया, जबकि शेष 740 मामलों को मैनुअल प्रक्रिया के जरिए निपटारा गया।

### NEWS BOX

#### ब्रजेश तिवारी बने नवयुवक दुर्गापूजा समिति के अध्यक्ष



**RANCHI :** नवयुवक दुर्गापूजा समिति बुकरू कांके की बैठक बुकरू स्थित श्री बजरंगबली मंदिर प्रांगण में हुई। मौके पर समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से ब्रजेश तिवारी को नव युवक दुर्गा पूजा समिति बुकरू कांके का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा सचिव अखिलेश तिवारी, उप सचिव पप्पू तिवारी, कोषाध्यक्ष अमरेश तिवारी, उप कोषाध्यक्ष हर्ष महली, मंत्री संजीत सुपरवार, महामंत्री अमर केशरी, पूजा प्रभारी राजेश सिंह, उप पूजा प्रभारी प्रकाश लोहरा, संरक्षक झुबला कश्यप, शशिराम, विजय कुमार, पर्यटन राम, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुजीत कुमार दुबे, प्रवक्ता रूपेश तिवारी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुरज राम, सदस्य सोनू साहू और राहुल तिवारी को बनाया गया है। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव युवक दुर्गा पूजा समिति बुकरू हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएगी। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। इस बैठक में समिति का विस्तार किया गया है। आगे समिति द्वारा बैठक कर पूजा की तैयारी की भी की जाएगी।

#### घनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन की परिवालन अवधि बढ़ी

**RANCHI :** रायचों की सुविधा के लिए दिवाली फेस्टिवल के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन संख्या 02832/02831 भुवनेश्वर-धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन वाया रांची की परिवालन अवधि में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों की समय सारणी, डिस्टांस एवं कोच संरचना पुनर्विचार रहेगी। ट्रेन संख्या 02832 भुवनेश्वर-धनबाद दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन वाया रांची यात्रा प्रारंभ दिनांक 19 अगस्त 2025 से यात्रा प्रारंभ दिनांक 30 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 02831 धनबाद-भुवनेश्वर पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन वाया रांची यात्रा प्रारंभ दिनांक 20 अगस्त 2025 से यात्रा प्रारंभ दिनांक एक दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन धनबाद से प्रस्थान करेगी।

#### 2128 स्कूलों में रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

**RANCHI :** झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असामयिक निधन पर रांची जिले के सभी स्कूलों में गहरी शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को जिले के 2128 स्कूलों में एक साथ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने दो मिनट का मौन रखकर दिग्गज मंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर छात्रों को बताया गया कि रामदास सोरेन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कार्य किया। शिक्षकों ने बताया कि मंत्री सोरेन हमेशा चाहते थे कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ सके। उन्होंने ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

#### वज्रपात से बचाव के लिए एमपीएलएस अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू, जागरूकता रथ को किया गया रवाना



**RANCHI :** सोमवार को जिला प्रशासन रांची द्वारा वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदा से जनहानि को कम करने के उद्देश्य से मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ लाईटिंग सेप्टी (एमपीएलएस) अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरु हो गया। इस समाह्वयित परिसर से उपायुक्त मंजुनाथ भजन्जी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर समाह्वीत रामनारायण सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वज्रपात से होने वाली क्षति को रोकने के लिए आम जनता के बीच सुरक्षा उपायों संबंधी जागरूकता फैलाना है। यह पहल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है और इसमें एमएस ग्लोबल मीडिया एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। जागरूकता रथ अभियान 18 अगस्त से 3 सितंबर तक छड़ियों को छेड़कर रांची जिले के चार प्रखंडों रातु, नामकुम, औरमांडी और सोनाहततु में चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड के चार-चार चिह्नित स्थलों पर विशेष सूचना सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये स्थल मुख्य रूप से स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजार परिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों को शामिल करते हैं, जहां आम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

#### 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली तैयारी को लेकर हुई बैठक

**RANCHI :** झारखंड में इस साल की सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची में होने वाली है। इसे लेकर आज उपायुक्त सह जिला डंडाधिकारी रांची, मंजुनाथ भजन्जी की अध्यक्षता में समाह्वयित मिडिया एमएस ग्लोबल मीडिया एक प्रमुख भागीदार के संभाग में एक बैठक हुई। बैठक में सेना भर्ती निदेशक, कर्नल विकास प्रदत्त माताधिकारी की सुझाव प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

#### वोट अधिकार यात्रा में प्रदेश कांग्रेस झोंकेगी ताकत

**RANCHI :** प्रदेश कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा में ताकत झोंकेगी। इस यात्रा में कांग्रेस कोट के मंत्री, विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केपाव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक मूल्यांकन एवं संधिना प्रदत्त माताधिकारी की सुझाव प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।





## फेसपैक रात के लिए

दिलिया से बने फेसपैक को रात में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काफी लाभप्रद होता है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच दिलिया लें। इसमें ऑयल की कुछ बूंद डालकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट में एक चम्मच शहद और 2-3 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगा लें। जब मिश्रण सूखने लगे तो स्क्रब कर लें बाद में निकाल दें। गर्म पानी से चेहरा धोएं।

### जब सिर में हो खारिश

केले में शहद मिला कर मसल लें। उसमें प्याज का रस मिला कर लें। फिर इसे बालों की जड़ों में लगा कर 20 मिनट तक छोड़ दें और बाद में शैंपू कर लें। इस मास्क से रूसी खत्म होगी। जै तून का तेल लें और उसे गरम करें। उसमें शहद की कुछ बूंदें डालें और उससे सिर की कुछ देर मसाज करें। बीस मिनट के बाद सिर को शैंपू से धो लें। खारिश दूर हो जाएगी।



## हाथों को सुंदर बनाने के टिप्स

खूबसूरत हाथ सभी को आकर्षित करते हैं। अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए आप मेनिक्चर करवा कर हाथों को हमेशा नर्म और मुलायम बना सकती हैं। हाथों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जानें ये मेनिक्चर टिप्स-



हाथ रखे होने पर आप इनमें तेज खुशबू वाला लोशन लगाएं। अक्सर नेलपॉलिश हटाने के बाद नेल्स सूखे हो जाते हैं ऐसे में आप नेल रिमूवर में कुछ बूंदें जोजोबा ऑयल की डालें और इसे नेलपॉलिश हटाने के बाद नाखूनों पर लगाएं।

नेलपॉलिश को ज्यादा दिनों तक फ्रेश बनाए रखने के लिए शीशी के मुंह पर क्यूटिकल ऑयल लगाएं और शीशी बंद कर दें।

गीले हाथों पर नेल फाइलिंग न करें, क्योंकि गीले होने पर नाखून कमजोर हो जाते हैं। नाखूनों को एक ही दिशा में फाइल करें नहीं तो वे टूट भी सकते हैं।



## घर सजाओ कुछ हटकर

होम डेकोर में कुशन, कर्टन, बेड कवर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनसे आप कम समय में घर का मेकओवर कर सकती हैं, इसलिए अलग-अलग उत्सव के लिए खास कलेक्शन रखें।

दीवारों पर सॉफ्ट कलर का पेंट है, तो एक्सेसरीज ब्राइट कलर की और दीवारों का कलर हाईलाइट करना हो, तो एक्सेसरीज सॉफ्ट रखें। घर का लुक अच्छा आता है।

पहले ही डिजाइड कर लें कि आपको कमरे का लुक एथनिक चाहिए या फिर मॉडर्न। इस बात को ध्यान में रखकर ही कमरे को सजाने की शुरुआत करनी चाहिए। कुशन और बेड कवर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अजकल मार्केट में कई तरह के कुशन कवर्स और बेड कवर्स उपलब्ध है जो आपके कमरे की सजावट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। दीवारों पर भी रंग कुछ हटकर चुन सकते हैं। इससे कमरे की काया ही बदल जाएगी।

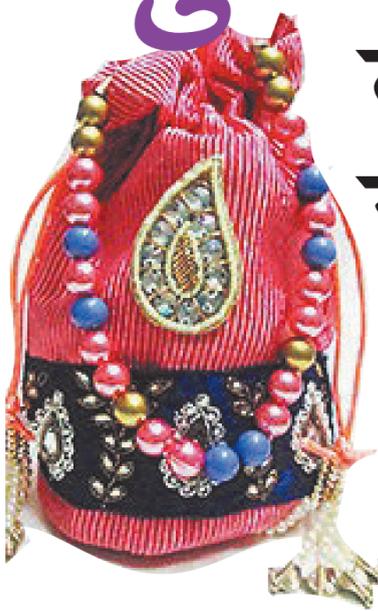


## डाइनिंग टेबल डेकोर

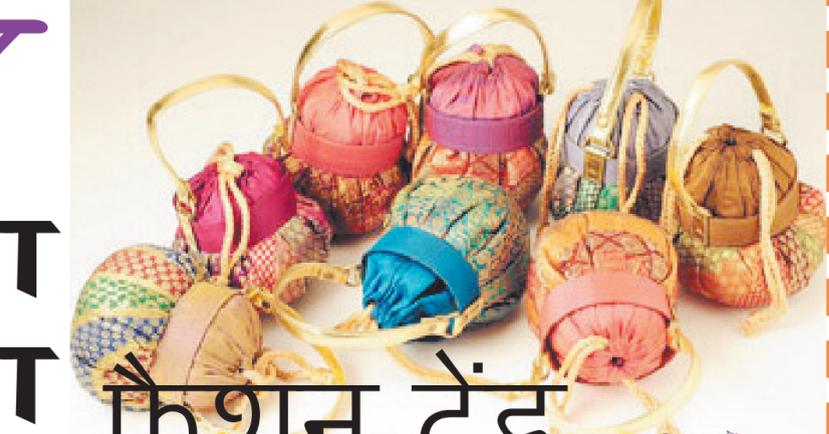
घर की शोभा बढ़ाने में डाइनिंग टेबल का भी बड़ा हाथ होता है। डाइनिंग टेबल से लिविंग रूम की शोभा चार गुना बढ़ती है और अगर यह ठीक से अरेंज हो तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। डाइनिंग टेबल सैट करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. डाइनिंग टेबल साफ रखें। अपनी डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ रखें। अगर आपके घर पर पार्टी है या फिर गेस्ट आने वाले हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल को पोंछ कर ही उस पर नैपकिन और प्लेट्स सजाएं।
- \* डाइनिंग टेबल पर टेबल मैट ऐसा होना चाहिए चाहिए जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ-साथ साफ करने में भी आसान हो।
- \* टेबल पर बीच-बीच एक सेंटर पीस रख देने से टेबल पर रखे अन्य समान अपनी जगह पर ठीक से अरेंज हो जाएंगे। सेंटर पीस के रूप में आप फूलों का वास या शो पीस आदि रख सकती हैं। अगर आपको सेंटरपीस नहीं रखने का मन है तो आप वहां पर नैपकिन का सेट भी रख सकती हैं।
- \* कटलरी परोसे गए खाने के आइटम के हिसाब से होनी चाहिए। इसे बाहर से अंदर के हिसाब से रखना चाहिए।
- \* डाइनिंग टेबल पर ज्यादा भीड़ न लगाएं। डिनर के लिए अपने डाइनिंग टेबल को यूजर फ्रेंडली बनाइए। वहां पर केवल वही चीजें रखें जिनकी जरूरत हो।

## बटुआ बना नया



यह सच है कि फैशन हर पल बदलता रहता है। इन दिनों बटुओं को सबसे ज्यादा फैशन है। जहां पहले लड़कियां बड़े बैग्स कैरी करना पसंद करती थीं वहीं इन दिनों बड़े बैग की जगह उनके हाथों में छोटा बटुआ देखने को मिलता है। कमाल की बात यह है कि ये बटुए हर शोप, साइज और रंग में मिलते हैं। इन बटुओं की खासियत यह है कि इन्हें आप हाथ में रख सकती हैं और साथ ही जब चाहें कंधे पर टांग भी सकती हैं। यह हर ड्रेस के हिसाब से मैचिंग की जा सकती है।



अब आपको इंडियन आउटफिट पसंद हो या वेस्टर्न बटुआ हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। बटुए अब हर तरह के मैटीरियल में उपलब्ध हैं। लैटर, रेक्सिन, जूट, कपड़े में यह मार्केट में पाए जाते हैं। एम्ब्रॉइडरी, सीक्सेस वर्क, स्टोन वर्कआदि हर रूप में पाया जाता है। बटुआ हर एज ग्रुप को इम्प्रेस करता है। चहे फिर वह कॉलेज गॉइंग गर्ल्स हो या फिर हाउसवाइफ या फिर वर्किंग वुमन। यह सबका फेवरिट है।



## लंबे समय तक रही अगस्त क्रांति की धमक

अगस्त क्रांति की शुरुआत 1942 में आठ अगस्त को हुई और कुछ दिनों बाद देश में कई जगहों पर उसका असर साफ तौर पर देखा गया। कुछ घटनाएँ तो इतिहास में अमर हो गईं, जब कई जगह स्थानीय लोगों ने अपने को आजाद करा लिया और अपनी प्रशासनिक इकाइयाँ गठित कर लीं। अपने यहां जिले भर में हिंसक कार्रवाई के बाद 19 अगस्त को स्थानीय नेता चित्तू पांडेय को जिला कलेक्टर बनाए जाने के साथ बलिया स्वाधीन हो गया था। बाद में अंग्रेजी सेना और पुलिस के अमानुषिक अत्याचार से वहां की कुछ दिनों की आजादी का दमन कर दिया गया। देश के पूरब में मेदिनीपुर और पश्चिम में सतारा जरूर लंबे समय तक आजाद रहे। फिर गांधी जी के कहने के बाद सम्पूर्ण देश के साथ एकजुटता के लिए वहां की सरकारों भंग की गईं। यहां देखा होगा कि मेदिनीपुर और सतारा के कुछ अंचलों में छापामार संघर्ष के बाद स्थानीय सरकारों ने सत्ता संभाली थी। बलिया थोड़ा अलग रहा, जहां अंग्रेजी सरकार के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी उसकी कुर्सी से हटाकर पूरे जिले की सुनिश्चित सरकार बनाई गई। तब स्वाधीन बलिया के पूरे जिले में मुख्यालय के आदेश माने गए। वहां कलेक्टर के साथ ही पुलिस कप्तान, तहसीलदार और थानेदार की कुर्सियों पर भी स्थानीय नेता काबिज थे। हां, बलिया, मेदिनीपुर और सतारा, तीनों जगहों पर एक समानता थी। तीनों जगह सरकारी खजानों के धन से कर्मचारियों को वेतन आदि देने आदि का काम किया गया, तो आगे की व्यवस्था चलाने के लिए पंचायत, कृषि केंद्र और अन्य तंत्र स्थापित किए गए। तत्कालीन बंबई (संप्रति मुंबई) के ग्वालिया टैक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद महात्मा गांधी 1945 तक किसी सार्वजनिक सभा में नहीं बोले। कारण यह कि वे जेल में बंद थे। इसके बावजूद उस ऐतिहासिक भाषण ने ऐसा कर दिखाया, जो भारत की आजादी का मार्ग बन गया। गांधी और अन्य नेताओं की तरह देशभर में लोग गिरफ्तार होते रहे और उनकी जगह नए लोग आ खड़े हुए। स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह भाषण मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस महासमिति अधिवेशन के पहले दिन सात अगस्त को दिया गया था। इस भाषण में करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव अगले दिन आठ अगस्त को पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार को ईंडिया वार कमेटी ने गांधी जी के सात अगस्त के भाषण के बाद करीब 24 घंटों तक इंतजार किया था। आठ अगस्त को अधिवेशन में गांधी जी के रखे प्रस्ताव के पारित होने के बाद रात में गांधी सहित तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उस दौर में जब संसार के सीमित साधन थे, अमले दो दिन लोगों तक इस भाषण के मंतव्य पहुंचने में लगे थे। फिर तो नौ और 10 अगस्त से ऐसा कुछ शुरू हुआ कि लोगों ने गांधी जी के आह्वान को अपने ढंग से लिया और विदेशी दासता को उखाड़ फेंकने के रास्ते पर चल पड़े। इसी का परिणाम था कि तब के संयुक्त प्रांत का बलिया, बंगाल का मेदिनीपुर और बंबई प्रांत का सतारा आजाद हो गया। यानी संपूर्ण देश की स्वतंत्रता के पांच अथवा सात साल पहले इन स्थानों ने एक रास्ता दिखाया। निश्चित ही यह रास्ता गांधी जी की अहिंसा का नहीं रहा गया, पर बाद में गांधी जी ने भी माना कि ब्रिटिश अत्याचार की घटनाओं ने स्थानीय लोगों को हिंसा पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया। गांधी जी के करो या मरो के नारे के बाद 1942 के उस अगस्त में मिदनापुर का तामलूक और सतारा के कुछ हिस्से के लोगों ने बगावत कर दी। मिदनापुर के तामलूक में शुरूआती घटनाओं के बाद 17 दिसंबर, 1942 से सितंबर, 1944 तक जातीय सरकार (राष्ट्रीय सरकार) चलाई गईं। तब राहत कार्य, स्कूलों को अनुदान, आपसी समझौते के लिए अदालतें बनाना और धनी लोगों के कुछ पैसे जरूरतमंदों में बांटने तक के काम हुए। सतारा में क्रांति सिंह नाना पाटिल भूमिगत रहते हुए लंबे समय तक समानांतर सरकार (पत्रि सरकार) का नेतृत्व करते रहे। लोगों ने पुलिस को चकमा देकर हथियार ले लिए। गांवों में कमेटीयां बनाकर सरकार के समानांतर काम किए गए। भौगोलिक स्थिति के कारण ये स्थान अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे। इसके विपरीत, बलिया में लोगों ने अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। बलिया निवासियों ने कई जगह रेल लाइन उखाड़ फेंकी, थानों और कचहरियों पर कब्जे के बाद जिला मुख्यालय पहुंचकर जेल में बंद अपने नेताओं को रिहा कराया। फिर स्वाधीन बलिया की घोषणा हुई। अगस्त क्रांति शुरू होने के बाद देश के कुछ अलग हिस्सों में बगावत की कोशिशें हुईं। दरअसल 1905 में जापान से रूस की पराजय, आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम और 1917 में रूसी क्रांति ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत में भी सशस्त्र विद्रोह की आकांक्षा जगा दी थी। तभी स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और लोकमान्य तिलक आदि मनीषियों के चलते धार्मिक पुरस्त्थानवाद में थरो पकड़। इससे भारतीयों में अपनी सभ्यता के गौरव और फिर यूरोपीय शासकों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ा। यह जरूर हुआ कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के चलते बंगाल और पंजाब जैसे हिस्सों में सशस्त्र संघर्ष कम हुए। इसके बावजूद, यह आक्रोश सुलगता रहा और 1942 आते-आते महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक आंदोलन के दौरान भी एक हिंसक विद्रोह बन गया। इसी की परिणति अगस्त क्रांति के दौरान बलिया, मेदिनीपुर और सतारा में देखने को मिली। निश्चित ही ये स्थानीय बगावतें राष्ट्रीय महत्व की बन गईं और इन्होंने आजादी की राह आसान करने में मदद की।

### ANALYSIS



डॉ. मंजु कुमारी

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत-अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न-आभूषण और टेक्नोलॉजी सर्वाधिक रहे। वहीं अमेरिका से भारत में 45.33 बिलियन डॉलर का आयात हुआ, जिसमें कच्चा तेल, कोयला और विमान के पुर्जे शामिल हैं। अमेरिका लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी। ट्रेड की टैरिफ पॉलिसी का सीधा असर भारत के उन सेक्टरों पर पड़ेगा जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर माल भेजते हैं, जैसे कपड़ा, जेम्स-एंड-ज्वेलरी, फार्मा और आईटी सर्विस। लेकिन, कहानी का दूसरा पहलू भी है और यही पहलू भारत के लिए मौन जवाब का हथियार बन सकता है। ट्रेड वॉहे भारत को डेड इकोनॉमी कहें, मगर यही अर्थव्यवस्था दर्जनों अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान है। भारत में इन कंपनियों की गहरी पैठ है। इतनी गहरी कि उनके उत्पाद और सेवाएं भारतीय उपभोक्ता के रोजमर्रा के जीवन में घुल-मिल गए हैं। इनसे होने वाला मुनाफा सीधा अमेरिका के खजाने में जाता है। यदि भारत चाहे, तो वह इन कंपनियों पर टैरिफ, टैक्सेशन या नियामकीय शर्तों के जरिए दबाव डाल सकता है। अमेरिकी कंपनियों का भारत में कारोबार अरबों डॉलर में है और इन पर कोई भी चोट सीधे अमेरिकी शेयर बाजार, रोजगार और मुनाफे को प्रभावित करेगी। भारत में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी हर क्षेत्र में फैली हुई है। ई-कॉमर्स में अमेजन इंडिया, टेक्नोलॉजी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एपल। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) में कोका-कोला, पेप्सिको, प्रॉक्टर एंड गैबल या पीएंडजी, कोलगेट, फास्ट फूड में मेकडॉनल्ड, केएफसी, डोमिनोस। लाइफस्टाइल में नाइकी, लेविस, स्केचर्स, जीएपी

अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को आज के दौर में यदि किसी एक शब्द में बयान करना हो तो उसे रणनीतिक सहजीवन कहा जा सकता है। व्यापार, तकनीक, रक्षा और कुटनीति हर क्षेत्र में दोनों देशों के हित आपस में गहरे जुड़े हैं। लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के वर्षों में इस सहजीवन में टैरिफ का एक कांटा चुभो दिया है। कभी भारत को टैरिफ किंग और कभी डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप अब भारत से आने वाले सामान पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाते का एलान कर चुके हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत पेपल्टी के रूप में जोड़ा गया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि भारत रूस से तेल और हथियार वगैरें खरीदता है, और वगैरें अमेरिकी उत्पादों को भारत में बराबरी का मौका नहीं मिलता। यहां यह समझना जरूरी है कि आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका और भारत का रिश्ता कैसा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत-अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न-आभूषण और टेक्नोलॉजी सर्वाधिक रहे। वहीं अमेरिका से भारत में 45.33 बिलियन डॉलर का आयात हुआ, जिसमें कच्चा तेल, कोयला और विमान के पुर्जे शामिल हैं। अमेरिका लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी। ट्रेड की टैरिफ पॉलिसी का सीधा असर भारत के उन सेक्टरों पर पड़ेगा जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर माल भेजते हैं, जैसे कपड़ा, जेम्स-एंड-ज्वेलरी, फार्मा और आईटी



सर्विस। लेकिन, कहानी का दूसरा पहलू भी है और यही पहलू भारत के लिए मौन जवाब का हथियार बन सकता है। ट्रंप चाहे भारत को डेड इकोनॉमी कहें, मगर यही अर्थव्यवस्था दर्जनों अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान है। भारत में इन कंपनियों की गहरी पैठ है। इतनी गहरी कि उनके उत्पाद और सेवाएं भारतीय उपभोक्ता के रोजमर्रा के जीवन में घुल-मिल गए हैं। इनसे होने वाला मुनाफा सीधा अमेरिका के खजाने में जाता है। यदि भारत चाहे, तो वह इन कंपनियों पर टैरिफ, टैक्सेशन या नियामकीय शर्तों के जरिए दबाव डाल सकता है। अमेरिकी कंपनियों का भारत में कारोबार अरबों डॉलर में है और इन पर कोई भी चोट सीधे अमेरिकी शेयर बाजार, रोजगार और मुनाफे को प्रभावित करेगी। भारत में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी हर क्षेत्र में फैली हुई है। ई-कॉमर्स में अमेजन इंडिया, टेक्नोलॉजी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एपल। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) में कोका-कोला, पेप्सिको, प्रॉक्टर एंड गैबल या पीएंडजी, कोलगेट, फास्ट फूड में मेकडॉनल्ड, केएफसी, डोमिनोस। लाइफस्टाइल में नाइकी, लेविस, स्केचर्स, जीएपी

और बैंकिंग में सिटीग्रुप ये सभी कंपनियां आज भारत में बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही हैं। उदाहरण के लिए अमेजन इंडिया का भारत में वार्षिक कारोबार 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच आंका जाता है, जबकि कोका-कोला और पेप्सिको का संयुक्त भारतीय कारोबार 4 बिलियन डॉलर से अधिक है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की भारतीय इकाइयां मिलकर सालाना 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का राजस्व अर्जित करती हैं। इनमें से कई कंपनियां न केवल बिक्री से बल्कि भारतीय आय का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजा जाता है। गूगल के लिए भी भारत वित्तीय बाजार में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिससे सालाना अरबों डॉलर की आमदनी होती है। इसी तरह से फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेक्टर में

अमेरिकी कंपनियों का दबदबा इतना है कि अगर भारत टैरिफ या प्रतिबंधात्मक कदम उठाए तो यह भारतीय उपभोक्ता बाजार के संतुलन को हिला सकता है। कोका-कोला और पेप्सिको को मिलकर सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा रखते हैं। प्रॉक्टर एंड गैबल और कोलगेट भारतीय टॉयलेटरीज बाजार में क्रमशः 20 और 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। नेस्ले जो स्विस् मूल की है, लेकिन अमेरिकी साझेदारियों से भी जुड़ी है का मैगी नूटल्स सेगमेंट में लगभग 60 प्रतिशत मार्केट शेयर है। फास्ट फूड सेगमेंट की बात करें तो मेकडॉनल्ड, केएफसी डोमिनोस और स्टारबक्स भारतीय स्थान बना चुके हैं। डोमिनोस अकेले ही भारत में सालाना 1.5 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है, जबकि स्टारबक्स ने भारत में प्रवेश के बाद से प्रीमियम कॉफी बाजार को लगभग अपने कब्जे में कर लिया है। लाइफस्टाइल और फैशन सेक्टर में नाइकी, लेविस और स्केचर्स जैसे ब्रांड भारतीय युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। लेविस का भारत में वार्षिक कारोबार करीब 300

मिलियन डॉलर है, जबकि स्केचर्स का भारतीय फुटवियर बाजार में 5 प्रतिशत हिस्सा है और यह तेजी से बढ़ रहा है। गैप और गेस जैसे ब्रांड प्रीमियम और लक्जरी सेगमेंट में खास पहचान रखते हैं। इन सबके बीच बैंकिंग और वित्त क्षेत्र भी अमेरिकी मौजूदगी से अछूता नहीं है। सिटीग्रुप का भारत में कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में मजबूत नेटवर्क है। सिटी इंडिया, जिसे आधिकारिक तौर पर सिटीग्रुप के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। भारत में, यह सिटी इंडिया के रूप में काम करता है, जो एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसके पास लगभग 25 लाख क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और भारतीय बाजार से सालाना करीब 1 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित करता है। अगर भारत अमेरिकी टैरिफ के जवाब में इन कंपनियों पर आर्थिक चोट करना चाहे तो इसके कई रास्ते हैं। पहला, अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाएं और वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएं। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन, उपभोक्ता सुरक्षा और पर्यावरण मानकों को सख्ती से लागू करना, जिससे उनके परिवारजन लागत में वृद्धि हो। तीसरा, स्वदेशी ब्रांडों और स्टार्टअप को सरकारी प्रोत्साहन देकर अमेरिकी ब्रांडों की निर्भरता घटाना। चौथा, सरकारी खरीद और रक्षा अनुबंधों में अमेरिकी कंपनियों की प्राथमिकता कम करना। स्वभाविक है, ऐसे कदमों के वैश्विक असर भी होंगे। सबसे पहले, इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी, हालांकि यह भी सच है कि भारत के लिए अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना कोई आसान फैसला नहीं होगा।

## 36 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला लाभ

बीते कई वर्षों से देश के किसानों को भारी वर्षा होने से नुकसान होता रहा है। इससे वह आर्थिक संकट का सामना करते रहे हैं। वैसे तो भाजपा की सरकार वर्ष 2014 में बनी थी और सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, लेकिन अधिकतर किसान इसके प्रति जागरूक नहीं थे। इसका फायदा नहीं ले पा रहे थे और इसके अलावा जिन्होंने यह योजना ले इसका फायदा लें, वह इसके प्रति जागरूक नहीं थे। इस वर्ष 29 जून से किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए अभियान चलाया गया। इसका लाखों किसानों का सीधे तौर पर फायदा भी मिला। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इस वर्ष किसान पीएम फसल बीमा

योजना पर अधिक जोर दिया गया। इस योजना के जरिए हाल ही में हुई भारी वर्षा के दौरान फसल बर्बाद होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिली। इसके लिए जिन किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना ली हुई थी, उनको सीधा लाभ मिला। जिसका भी नुकसान हुआ उसे केंद्र सरकार की ओर से भरपाई की मिली। अधिकतर किसान तो सिर्फ यह समझते हैं कि इस बीमा के तहत केवल बारिश से बर्बाद होने वाली फसल के लिए एमआयवा मिलता है, लेकिन बात दें कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बे-मौसम बारिश, फसलों की सूखा, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इश्योरेंस कवर देना है। अब तक करीब 36 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री

फसल बीमा योजना के नौ साल पूरे हो गए। योजना को तो बहुत समय हो चुका, लेकिन इसके लिए किसान बहुत धीरे जागरूक हुआ लेकिन अब स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है। देश में किसानों को लेकर हमेशा बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है। विपक्ष हमेशा उनकी असंतुष्टि को लेकर सभी पहलुओं को उजागर करता है। दूसरी ओर सत्ता में बैठे सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन इन दोनों के बीच हम एक चीज भूल जाते हैं कि सरकार कोई भी हो वह अनन्दाता के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। किसानों से जुड़े मुद्दे पर कुछ लोग गलत तरह की राजनीति करते हैं जिससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। लेकिन, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में किसानों पर राजनीति न करते हुए उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक किया करें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1995 से

2014 के बीच 296438 किसानों ने आत्महत्या की थी व 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 100474 थी। इन आंकड़ों से यह तो पता चलता है कि इजाफा तो हुआ है, लेकिन समस्या का अभी पूरी तरह निदान नहीं हुआ है, परंतु धीरे-धीरे जागरूकता से अनन्दाता को संपन्नता मिलने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन इसकी रफ्तार को तेजी से बढ़ाना होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। भारत की लगभग तीन तिहाई से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। मतलब हम देश के उस व्यवसाय के प्रधान है जो लगभग पूरे देश के नागरिकों से जुड़ा है। वैसे तो आज भी हमारे पास कृषि करने के लिए बहुत

भूमि है लेकिन बढ़ती आबादी से अब कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। यदि महानगरों की बात करें तो बिल्डरों ने लगभग सारी जमीनों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली-पनसीआर की बात करें तो दिल्ली से सटी सभी सीमाएं जैसे गाजियाबाद का राजनगर, हरियाणा का गुरुग्राम, नरेला व लोनी, यहां बीते दो दशकों में खेती की जमीनों पर इतनी इमारतें बन चुकी हैं कि यहां सारी खेती व खाली जमीन खत्म हो चुकी। स्थिति यह है कि दिल्ली का मौसम भी इस वजह से प्रभावित होने लगा। किसानों की फसलें कई कारणों से बर्बाद हो जाती हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, कीटों और बीमारियों का प्रकोप, खराब बीज और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, बेमौसम

बारिश से गेहूं, चना और अन्य फसलें भीग सकती हैं जिससे वह खराब हो सकती हैं। फसलों पर कीटों और बीमारियों का हमला होने से भी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। जैसे कि कीटों के कारण बीज अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते या फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे फसल के लिए खेतों में जलजमाव से बचने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, जैसे कीटनाशकों का सही उपयोग। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि पानी का संरक्षण करना और सूखे प्रतिरोधी फसलों का उपयोग करना चाहिए। बहरहाल, किसानों को जागरूक करने व उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए।

## Social Media Corner

सब के हक में...

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। उनके प्रयास हमारे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।



(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। लेकिन आज वोट चोरी के जरिये इस बुनियादी अधिकार को छिना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। वोट चोरी बंद होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

(प्रियंका गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल आदेश्वर बुजौरजी तारापोर जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। 1965 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता, नेतृत्व और अटूट साहस से दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई तथा रणभूमि में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शौर्यगाथा भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो आज वाली पीढ़ियों को संघर्ष राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रेरित करती रहेगी।



(ओम बिड़ला का 'एक्स' पर पोस्ट)

## गाजा में दम तोड़ती इंसानियत और तमाशबीन दुनिया

हम लगभग हर दिन उन फिलस्तीनियों पर गोलियां चलने के मामले देख रहे हैं, जो भोजन की तलाश में सहायता केंद्रों तक पहुंचते हैं या वहां से लौटते हैं। कई बार ये गोलियां सहायता केंद्र के भीतर खड़े लोगों पर चलाई गईं, तो कई बार वे लोग निशाना बने, जो भोजन या आटे का बोरा लेकर अपने घर लौट रहे थे। यह कहना है भुखमरी के बीच घेरे में फंसे गाजा के डॉक्टरों का। सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया रूकेगी या गाजा के सर्वनाश तक जारी रहेगी। एक बात और, इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या वह गाजा की महिलाओं और बच्चों को मारकर हासिल हो सकती है। अंतिम प्रश्न यह कि क्या दुनिया ने अपनी आंखें यह मानकर मूंद ली है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर उसकी आंखें खुली हैं और यह मान लिया गया है कि जंग में सब जायज है। 7 अक्टूबर, 2023 को हममास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद चली कार्रवाई में हममास के तमाम बड़े नेता मारे जा चुके हैं और जो शेष हैं, वे केवल 10 से 15 प्रतिशत इलाकों तक सिमटे हुए हैं। हिजबुल्ला निष्क्रिय है और ईरान ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। मगर, जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर युद्ध रूकवाकर समाधान निकालने की जिम्मेदारी है, वे पंगु से दिख रहे हैं। जो देश स्वयं को मानवाधिकारों के मसीहा कहते हैं, वे इजरायल

को ही मदद कर रहे हैं। फिलस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें, तो अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से 60,839 लोग मारे जा चुके हैं और 72,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन कार्रवाइयों में गाजा की 60 प्रतिशत से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और करीब 20 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिनमें से अधिकांश गाजा पट्टी के केंद्रों में टूट-टूटकर रहे गए हैं। इजरायल अब गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित व्यवस्था को भी दरकिनारा कर रहा है। वह चाहता है कि आपूर्ति के लिए एक कॉरिडोर बने, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित व्यवस्था का लाभ हममास न उठा सके। वधपि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के उप महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने चेतावनी दी है कि यह योजना गाजा में पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर देगी। इजरायल अभी विराम लगाने की मन-स्थिति में नहीं दिख रहा। वह गाजा का अस्तित्व फलस्तीन के रूप में समाप्त करना चाहता है। यही वजह है कि उसके रक्षा मंत्री काट्ज ने गाजा के नागरिकों को एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी तक सीमित करने की योजना बनाई है। यह सिटी गाजा के दक्षिणी रफाह के खंडहरों पर बसेगी, जिसमें शुरू में लगभग छह लाख बेघर हुए फलस्तीनियों को स्थानांतरित किया जाएगा, तत्पश्चात 20 लाख लोगों को। इसके पीछे इजरायल का मकसद है,

हमास सदस्यों को गाजा के लोगों से दूर रखना। इस सिटी के संचालन का दायित्व अंतरराष्ट्रीय संगठनों का होगा, लेकिन नियंत्रण इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) का। इस योजना के खिलाफ 16 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों ने पत्र लिखा है, जिसमें इसे स्पष्ट रूप से अवैध बताया है। उनके अनुसार, यह नस्लीय विनाश का एक तरीका है। गाजा में मरने वालों में पत्रकारों के नाम भी शामिल हो गए हैं। बीते रविवार की रात गाजा शहर में इजरायली हमले में अल जजीरा के पत्रकारों की मौत हो गई। अलजजीरा के अनुसार, मारे गए पांच पत्रकारों में से चार उसके नेटवर्क से जुड़े थे। लेकिन इजरायली सेना ने अल जजीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ को हममास का आतंकी बता दिया। सच क्या है, यह कहना मुश्किल है। उधर कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि इजरायल यह सब योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है, ताकि गाजा में भुखमरी की कवरेज न हो सके। बहरहाल, गाजा की इस स्थिति के लिए पूरी तरह से दोषी कौन है, यह मूक-सी दिख रही दुनिया को तय करना है। दोषी जो भी हो, लेकिन इजरायल को यह समझना होगा कि इस पूरे संघर्ष में मां की गोद में भूखा बच्चा विजय का नहीं, बल्कि त्रासदी का प्रतीक है और यह उसके खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है।

## कुत्ते और कानून

सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला छुट्टा-धूमनेवाले कुत्तों के मामले में अब तक का सबसे सशक्त न्यायिक हस्तक्षेप है। दिल्ली और इसके उपनगरों को आठ हफ्ते के भीतर हर आवारा कुत्ते को पकड़ने, उन्हें स्थायी रूप से बाड़ों में बंद करने और तेजी से आश्रय क्षमता बढ़ाने का निर्देश देकर, शीर्ष अदालत ने प्रशासनिक काहिली नहीं चलने देने का संकेत दे दिया है। दिल्ली में एक साल में कुत्ता काटने के लगभग 30 हजार मामले दर्ज होते हैं और संक्रमण-रोधी उपचार तक असमान पहुंच के चलते रेबीज अब भी गरीब शहरी बाशियों की जान ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट का यह डंडा पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 के साथ टकरावपूर्ण है, खासकर इसके पकड़ो, बधिया कर, टीका लगाओ, छोड़ो सिद्धांत के साथ। यह नियमावली नगरपालिकाओं को स्वस्थ कुत्तों को स्थायी रूप से दूसरी जगह ले जाने या लंबे समय तक बाड़ों में बंद रखने से रोकती है, सिवाय उस स्थिति के जब कुत्ता रेबीजग्रस्त हो, लाइलाज रूप से बीमार हो या पशु चिकित्सक द्वारा खतरनाक रूप से आक्रामक पाया गया हो। हालांकि, नियमावली आंकड़ों की कसौटी पर नाकाम रही है। छिटपुट बंध्याकरण अभियानों के बावजूद शहरों में कुत्तों की आबादी बढ़ती रही है, क्योंकि 70 फीसदी कवरेज लगभग कहीं नहीं पहुंच पाया है और यह इससे नीचे रहने पर प्रजनन फिर उसी स्तर पर आ जाता है। कुत्तों को उनके इलाकों में लौटाने के नुस्खे से उन्हीं उच्च-सघनता वाले मोहल्लों में झुंड बन गये हैं, जहां बच्चे खेलते हैं और कूड़ा जमा होता है। यह नियमावली नगरपालिकाओं को वैकल्पिक रणनीतियां, जैसे लंबे समय के लिए बाड़ों में बंद करना, अपनाने से भी रोकती है। अगर नियमावली जस की तस रही, तो कुत्तों को कैद करने वाले नगरपालिका अधिकारियों पर मुकदमा हो सकता है। अगर वे नियमावली का पालन करते हैं, तो उन पर अदालत की अवमानना का खतरा है।

## Needed: A new satyagraha for peace

At a time when war seems to be a daily occurrence and an easy accompaniment to the nation state, thinking of peace is urgent.

One has to begin with a set of indirect observations. Literary critics have mentioned that poetry sometimes not only provides an aesthetics of insights, but can capture the truth of an event in a way social science is rarely able to. One wants to echo, in particular, the words of Jesuit poet Gerard Manley Hopkins, who said, "Piecemeal peace is poor peace." One has to, first of all, begin by understanding that peace is not a question of fragmentary understandings. It's in this context that one must begin by understanding what psychologist Ashis Nandy has repeatedly emphasised. Nandy emphasised the impoverishment of international relations as a set of conceptual frameworks for capturing the idea of peace. He said international relations rely on fragmentary concepts like borders, securities, and contracts—none of which is able to create an organic sense of peace. It's like expecting a cost-benefit analysis to create a commons. It's in this context that Ela Bhatt has argued that we have to go beyond dualism, particularly surrounding the idea of international relations. For this, we need to create a new kind of domesticity, one which encompasses international relations. She argued that being at home in domestic terms means being at home in the world—that the ideas of swadeshi and swaraj are both encompassed within the idea of peace. What is peaceful in the vernacular sense has also to be peaceful in the cosmopolitan sense.

This idea was taken up much earlier by Scottish biologist Patrick Geddes. He began by saying that the idea of peace requires not only a holistic worldview, but also a holistic knowledge system. Within this context, he pointed out that any idea of a knowledge system which is at peace with itself is both interdisciplinary, intercultural and international. His work ranged from contributions in urban planning to his work on Palestine and Ireland. One has to emphasise the importance of memory. Here, Nandy becomes important again, who said memory sometimes haunts the hostilities of the world. He pointed out that many of the people who worked on partition as a subject had not experienced it. Theirs was a voyeuristic memory appropriated from their grandfathers and grandmothers. Many of the current communal forces, too, have voyeuristic memories of partition—there is little that is authentic about it.

Beyond memory and ethics, another issue of great importance is the role of the exemplar. Peace needs a new paradigm, but this paradigm can only be found embodied in the work of exemplars. For this, we have to go beyond Trumpian politics to an understanding of peace through figures like Mahatma Gandhi and Dag Hammarskjöld. These exemplars embody the idea of peace in an absolutely individualistic and unique fashion, and yet capture the spirit of universality that needs to inform every level of peace.

The second point one has to make is the importance of sacredness. Peace cannot be a secular contract. What one needs is a notion of the sacred, a notion of the holy, a notion which, to a certain extent, defines the possibility for peace in terms of what we can touch and touch gently. It's in this context that Gandhi's work on satyagraha has to be revived in a more international framework. When Gandhi articulated his ideas, he did not encounter the idea of the concentration camp or certain kinds of violence. What we have to do today is to articulate how to stand up against violence, particularly the violence of terror. Satyagraha has to be reinvented, choreographed to create a new understanding of terror and how to blunt its threatening possibilities.

## Why Indians need to run for their lives

**Obesity and fatty livers are huge health concerns among Indians. Researchers across the world are cautioning against a 'sitting epidemic' of sedentary lifestyles that causes grave health issues. Apart from embracing active lifestyles, Indians need to be wary of junk food**

Get up, stand up, stand up for your rights," sang Jamaican star Bob Marley. But there is a new way to stand up for your rights—for public and personal health, not political awareness. If you are one whose work or habits keep you glued to a chair and involve staring long hours at a computer or mobile screen, there is official confirmation that your health may not be sitting pretty, quite literally. Union Health Minister J P Nadda confirmed to the Lok Sabha this month that a sample survey of technology workers in Hyderabad showed an overwhelming majority of them suffered from fatty liver disease, which can lead to various health complications. As much as 84 percent of the 345 employees surveyed had increased liver fat accumulation that indicated metabolic dysfunction, while another 34 percent had what is technically called metabolic syndrome, associated with diabetes and heart problems. That should give a stand-up call to all sorts of techies and associated new-age knowledge workers, not to speak of the ubiquitous smartphone addict. Nadda did not talk explicitly about the side effects of chair-bound work, but there is increasing global awareness, government action, and matching fancy expressions to show that there is a link between sitting, junk food, and bad health. There is a series of TED talks on what some call 'The Sitting Addiction', under which experts cover everything from outcomes to postures related to sitting.

Experts from America's National Institutes of Health say higher amounts of sitting time are associated with "greater risk of all-cause mortality". An Australian government advisory titled 'Why sitting is the new smoking' links sitting or lying down for too long to heart disease, diabetes, and some cancers, besides impaired mental health. The University of British Columbia describes sedentary behaviour as a 'Sitting Epidemic', as it calls out the adverse side effects of attending classes, joining meetings, and working on computers in general. It recommends vigorous physical activity of at least 150 minutes per week for most adults, spread evenly in 10-minute stretches. Such activity is good for both physical and cognitive functions, self-esteem, creativity, sleep and concentration, say the

Canadian university's experts. They even recommend impromptu dance parties as a solution. The flip side of this new awakening is junk food consumption. Things took a nationalist twist in India last month when the health ministry moved fast to deny reports that suggested the authorities were cracking down on the consumption of jalebis, laddoos and samosas, which are the first-choice snacks for any celebration north of the Vindhya.

The ministry said it had only issued an advisory towards making "healthier choices at workplaces" as it asked for display boards in canteens, cafeterias and meeting rooms to raise awareness on the harmful consumption of



hidden fats and excess sugar to check obesity. "Munch responsibly" may well be a latter-day equivalent of slogans on avoiding the ill effects of alcohol. The ministry, up against patriotic foodies, clarified it "does not target India's rich street food culture". You may order some chhole bhature to celebrate such support for culinary rights, but the science of it all is still bothersome. The Union government's orders are in line with the World Health Organization's nutritional criteria published two years ago, which aim to protect children from marketing that promotes unhealthy food.

Sedentary adults and eager gourmands also need some official push, as has been evident worldwide. At least two Indian states and several countries, especially in Latin America, have over the years declared fiscal or legislative wars on junk food. Bihar and Kerala had imposed taxes on junk food sales a decade ago. Labelling unhealthy junk food and taxes on sugary drinks have been among common measures in a few countries. Chile banned junk food in schools. Japan in 2008 imposed a 'Metabo' tax under which companies and departments were penalised if their staff had waistlines exceeding stipulated limits. Under the Metabo Law that advocates annual check-ups for those between 40 and 74 years of age, men should have waistlines below 90 cm and women under 85 cm. Those measuring above these are given motivational messages and counselling to shape up. All that is happening amid the pharmaceutical industry's efforts to check obesity with 'wonder drugs'. Health authorities advise caution in the use of anti-obesity drugs like Ozempic, intended primarily for diabetics and insulin-dependent people, but increasingly used as an easy proxy for diet control. Social media influencers who promote anti-obesity drugs probably make matters worse, though some influencers do talk of the risks involved. A side effect of anti-obesity drugs is the way some reduce appetites, giving a new headache (or is that stomachache?) for restaurant owners. A recent article in The New York Times speaks of eateries serving up smaller meals and "tasting menus" to cater to a new lifestyle option linked to the rise of Ozempic.

One silver lining in this dark cloud made up of fatty deposits is that artificial intelligence, the new economic pandemic that threatens to kill techie jobs, may well be a blessing in disguise. I say this with chronic optimism. Maybe there is a divine signal from up there to see a healthy reverse swing in the AI threat. Running for your life may not be a bad idea at all.

## Onus on community leaders to end child marriages

**Being pushed into the role of wife and mother at an immature age plays havoc with their health and stunts their growth as individuals and contributors to society**

A disturbing trend that increased during the Covid pandemic appears to be here to stay. Child marriages, which mainly result from economic distress, have risen dramatically over the past few years in Karnataka. The state clocked a shocking 700 cases in 2024-25, surpassing all other states. The trend became visible in 2020, when Karnataka reported 184 cases; it recorded 276 cases in 2021-22, 418 in 2022-23, and has been ahead of Assam and West Bengal, other states with a large prevalence of child marriages. The districts of Chitradurga, Mysuru, Shivamogga and Haveri have recorded high numbers, with teenage pregnancies as an unhealthy fallout of these marriages. While there are many brave schoolgirls who stand up for their rights—like a minor from Challakere taluk of Chitradurga district who took the help of police—many more buckle under pressure. This shift in the social structure flies in the face of claims of development made by the central and state governments, especially in a progressive state like Karnataka. This gendered development impacts only girls, who are still viewed as a burden until their marriage. It is also a pointer



to the fact that more girls are dropping out of school. Being pushed into the role of wife and mother at an immature age plays havoc with their health and stunts their growth as individuals and contributors to society.

To give due credit, Karnataka has brought in a number of

measures to end the scourge: it has deputed 59,000 child marriage prohibition officers to backward regions to avert surreptitious ceremonies and raise awareness, instituted a cash award for gram panchayats which bring down the number of child marriages to zero, and there is also the 24/7 national helpline. The state now proposes to amend the Prohibition of Child Marriage Act to criminalise child marriages and even attempts to organise child engagements, which will attract a prison term of up to two years and a fine of ₹1 lakh. It is puzzling that despite such measures, the practice continues. Quite often, it is local officials who delay action, or look the other way, condoning the practice. The onus should also be on community leaders and panchayats to stop such incidents.

Education and awareness are the keys to eradicate this malaise. If the government fails to take swift and decisive action, it could drag Karnataka down the human development index and push it back a few decades.

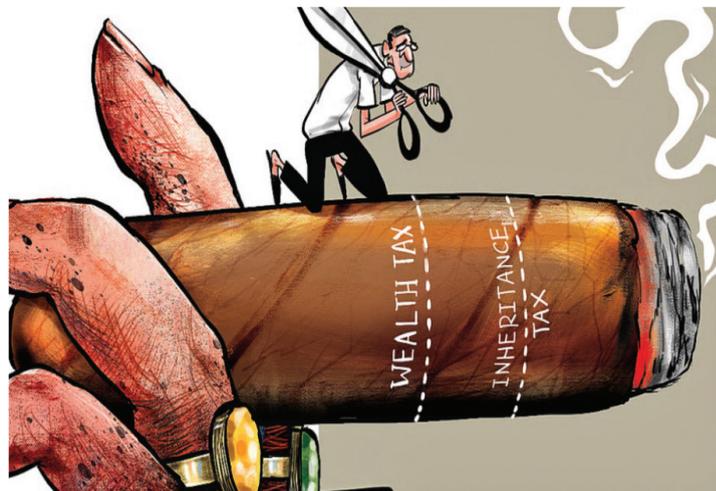
# Nothing utopian about it: Rethinking poverty in India

**India@79 | Capitalism is dispossessing the peasantry from their land but not absorbing them in industrial labour in adequate numbers. The State has responded with disaggregated welfare handouts. But there are other ways to ensure the fundamental rights of the poorest**

To read the pervasive commentary in the economic sections of the world's newspapers on what the globalising neoliberal turn in political economy has wrought in the last four decades or so in the Global South, one would think it has all been for the good—their economies have been uniformly growing, as has their middle class, and their poverty has been reduced. In the case of India, there is constant talk of it as poised to become a great economic power in the near future, to say nothing of its prestige on the international canvas as a nuclear power. Yet, serious economic analysis has fundamentally challenged this as, in one crucial respect, downright false. Measurement of poverty in India, by criteria that are sound rather than skewed, points to increased immiseration of the worst-off in numbers as large as ever, despite a swelling middle class. A puzzle arises then as to why, given this growing immiseration, there has been no explosion of social unrest. A familiar answer points to how populations are deflected from their suffering by the politics of identity, Hindutva politics in India being a conspicuous example. There is, no doubt, no such truth in this. But deflections of that sort cannot for long prevent the intolerability of the suffering—especially if it is as

extreme as studies have shown it to be—from prompting popular anger and agency. So, the puzzle remains. In recent years, the influential work of economist Kalyan Sanyal implies a different explanation. Its argument in summary form is this. Capitalism in recent decades in countries like India dispossesses the peasantry from their land but cannot absorb them in industrial labour, as was done in Europe in earlier centuries (nor even in what Karl Marx called the 'reserve army'). It thus creates a very large population that is outside of the corporate capitalist political economy, hence unable to morph into a unified class formation with the familiar potential for forging the agencies of resistance attributed to the 'proletariat' in an earlier phase of capitalism. But, Sanyal argues, at least in democratic societies, the State cannot ignore their condition to the point that they simply will perish in large numbers. Invoking ideas from philosopher Michel Foucault, Sanyal suggests that in our neoliberal times various 'governmental technologies' respond to the demands made in a very disaggregated form (there being no unified proletariat with the cement of internal solidarities) by different sections of this immiserated population—some seeking shelter as squatters, as it might be, others seeking loans till they are able to find some work, yet others seeking cash transfers or direct delivery of food to meet the most elemental needs. These are, essentially, ameliorative accommodations that various state

institutions—national or regional—make when the demands for them from one or another section of the population seem unignorable and, qua accommodations, they are not always subsumable under the framework of what the law permits. It may often be that the State's motivations for these arrangements are to gain electoral favour from that particular demographic.



Such claims for 'governmentality', thus, can be seen as directly addressing the puzzle I have raised. But it is important to find the right description of the model it posits, and not to see it as claiming more than it does. If these ameliorations end up being too big a strain on

capitalist accumulation, they may well be withheld by the State and the capitalist economies that States by and large serve in democratic societies. (Indeed, we might view Donald Trump's deportations of immigrants today as seeking to reverse the previous governments' accommodations of undocumented immigrants—a case of finessing the law, which the model recognises—claiming that they are a drain on capital accumulation, removing which would accrue more benefits for citizens 'proper'.) The model is thus delicately poised, a sort of equilibrium fulfilling opposing demands—of capital and those that capital renders most abjectly immiserated.

What would be wrong are the descriptions often given of the model as representing a critique of neoliberal capitalism. A highly deprived population group can resist the worst effects of neoliberalism by demanding and getting such accommodations; but that resistance does not amount to a critique of neoliberalism. There can be no notion of a critique of x that does not propose some method that can at least constrain—and perhaps, if the constraints are recursively developed, go on to undermine—x. But Sanyal describes accommodations within a neoliberal political economy. Constraining or undermining is not so much as sought.

No doubt, this modesty in what is sought owes to the fact that capital in our time is able to constantly destabilise more ambitious efforts of States to constrain capital so as to provide the most basic necessities to their citizens.

## ITR-6 excel utility now live: Who is eligible to file

**New Delhi.(Agency)**

The Excel utility for ITR Form 6 has now been released for AY 2025-26, enabling companies to file their income tax returns for FY 2024-25.

The Income Tax Department wrote on X, "Kind Attention Taxpayers! Excel Utility of ITR-6 for AY 2025-26 is now live and available for filing." WHO NEEDS TO FILE ITR-6?

ITR-6 is the return form used by companies that do not claim exemption under Section 11 of the Income Tax Act, which is meant for entities with income from property held for charitable or religious purposes. Corporate taxpayers can now prepare and file their income tax returns using the updated utility available on the e-filing portal.

Earlier this year, the government had already notified all ITR forms for AY 2025-26. The utilities for ITR-1 and ITR-4 were released in May and June, followed by ITR-2 and ITR-3 in July. The excel utility for ITR-5 was launched on August 8, and now ITR-6 has been added to the list. The tax department has also made it possible for taxpayers to file updated returns (ITR-U) for Assessment Years 2021-22 and 2022-23 in ITR-3 and ITR-4.

### INCREASED BURDEN ON EXPERTS

The staggered rollout of utilities has added to the workload of chartered accountants and experts, who already face several deadlines.

Many professionals feel that the delay will result in a rush to file returns, increasing the likelihood of errors. Incomplete or incorrect filings often draw queries from tax officials and may lead to penalties.

### TECHNICAL ISSUES STILL REMAIN

Although utilities are being released in phases, technical glitches are still troubling users. Some corporate taxpayers using ITR-2 have reported problems with the Annual Information Statement (AIS) and the Tax Information Summary (TIS).

Professionals say these issues should be resolved quickly, as last-minute adjustments could make the filing process even more difficult.

## Nikhil Kamath invests Rs 137.5 crore in Goldi Solar

**MUMBAI.(Agency)**

Entrepreneur and investor Nikhil Kamath has invested Rs 137.5 crore in Goldi Solar, India's largest solar photovoltaic (PV) module manufacturer, as part of efforts to strengthen the country's renewable energy manufacturing base. The fresh fund infusion will help Goldi Solar expand its production and accelerate India's positioning as a global renewable energy hub.

Over the last year, Goldi Solar has nearly tripled its module manufacturing capacity—from 3 GW to 14.7 GW—and is now ramping up its solar cell production facilities in Surat, Gujarat. The company plans to roll out new high-efficiency modules and cells using emerging technologies to meet India's fast-rising demand for clean power. Renewable energy in India is a massive sector, and there is an equally massive opportunity to build global-scale companies right here on our home ground. It is imperative that we back these companies to accelerate the country's clean energy transition," Kamath said.

The investment comes amid robust domestic solar demand, underpinned by the government's target of installing 280 GW of solar power by 2030, import duties on foreign modules, and incentives for local manufacturers under the Production Linked Incentive (PLI) scheme. Founded in 2011 by Ishverbhai Dholakia, Goldi Solar has grown into India's largest module manufacturer with state-of-the-art facilities in Surat. In less than a year, the company expanded capacity from 3 GW to 14.7 GW and is now venturing into large-scale solar cell manufacturing to serve both domestic and export markets.

## JSW Steel and POSCO plan joint venture for 6 MTPA steel plant in Odisha

**CHENNAI.(Agency)**

JSW Steel Ltd and South Korea's POSCO Group have signed a non-binding agreement to explore setting up a six million tonnes per annum integrated steel plant in India through a 50:50 joint venture. Odisha has emerged as the preferred location, though the final site will be decided after a detailed feasibility study.

This proposed project marks a major step forward in the partnership between the two companies. It follows an earlier memorandum of understanding signed in October 2024, where JSW and POSCO had agreed to collaborate on a five million tonne project in Odisha and explore opportunities in areas such as renewable energy and battery materials for electric vehicles.

Executives from both companies highlighted the strategic importance of the tie-up. Jayant Acharya, Joint MD and CEO of JSW Steel, said that combining JSW's strong execution capabilities in India with POSCO's technological expertise would create a competitive steel manufacturing hub catering to both domestic and international markets. Lee Ju-tae, President of POSCO Holdings, noted that India is central to future global steel demand and described the partnership as one built on long-term trust and a shared vision for industrial growth.

The companies will now conduct a detailed study to assess the location, investment structure, raw material requirements and regulatory approvals before taking a final investment decision. Industry analysts say the project could strengthen India's steel manufacturing capacity and support its ambitions of becoming a global hub for industrial production. It also signals POSCO's renewed interest in India after past plans were delayed due to land acquisition challenges. If completed, the project would represent one of the most significant Indo-Korean industrial collaborations and add momentum to India's goal of ramping up domestic steel output while also expanding its export potential.

# GST cut before Diwali These items likely to cost you less this festive season

**Prime Minister Narendra Modi gave the first indication of GST reforms in his Independence Day address from the Red Fort, calling it a "Diwali Bonanza."**

**New Delhi.(Agency)**

The government is preparing a major revamp of the Goods and Services Tax (GST) that could lower the cost of several essential and consumer goods. The Finance Ministry has been working on the new structure for more than six months, and officials say the revised rates may be rolled out around September or October, just ahead of Diwali, if approved by the

GST Council. Prime Minister Narendra Modi gave the first indication of this move in his Independence Day address from the Red Fort, calling it a "Diwali Bonanza." Government sources told India Today that work on GST rationalisation began the same day the Union Budget was presented, on February 1, 2025.

### ITEMS THAT COULD BECOME CHEAPER

Under the draft plan, several daily-use goods may soon cost less. Essential items such as ghee, butter, packaged foods, fruit juices, and packaged coconut water, which are currently taxed at 12%, could be shifted to the 5% GST slab. Similarly, footwear and apparel priced below Rs 1,000 are also likely to be moved to the 5% rate. A source told Business Today, "Common use and daily-use items will be in the 5% GST rate," suggesting that households could see immediate relief

once the changes are implemented. There is also discussion about lowering the GST on small cars and two-wheelers under



250cc from 28% to 18%. This could help revive demand in these segments, which have seen slower growth in recent years. Other goods such as air conditioners, dishwashers, televisions up to 32 inches, and cement are also expected to benefit from rate cuts. Cement, for instance, may move from the 28% slab to 18%, which

could reduce construction and housing costs. GST on health and life insurance premiums may also be reduced, possibly to 5% or even zero, down from the current 18%, reported news agency Reuters, citing their source. If approved, the tax cuts are likely to be announced before Diwali, in October, as that is usually the country's busiest shopping season.

### SIMPLER TAX STRUCTURE ON THE CARDS

Currently, GST rates fall under five main slabs: 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%, with compensation cess applied on certain goods. According to the proposal prepared by the GST fitment committee, this will be simplified to just two primary rates, 5% and 18%. The compensation cess is expected to be phased out and replaced with a flat 40% levy on a smaller list of items, mainly so-called sin goods such as tobacco and pan masala.

## Crorepati on paper, cash-poor in reality CA explains why liquidity matters more

**A high net worth can be misleading if most of your wealth is tied up in property or long-term investments. An expert believes that true financial security comes from having liquid assets that can be accessed at short notice.**

**New Delhi.(Agency)**

Many people proudly look at their salary slips, property documents or investment statements and assume they are financially secure. But by the middle of the month, they often find themselves struggling to manage day-to-day expenses. According to CA Apoorva Gavai, this is a common problem, even among high-income earners and those who own valuable assets. She wrote on LinkedIn, "Ever looked at your salary slip or property papers and thought, 'I'm doing well, only to feel broke by the 20th of the month? You're not alone. In my work with individuals and families across income levels, I've seen this often:

High net worth. Good job. Own house. Some investments. Still, constantly stressed about money." So why does this happen if the numbers on paper look strong? The answer lies in the



difference between net worth and cash flow.

### NET WORTH VS MONEY IN HAND

Net worth is what you own minus what you owe. But cash flow is the income you actually have left after covering your monthly expenses. For example, if you own a flat worth Rs 1.5 crore and have a Rs 50 lakh home loan, your net worth would be Rs 1 crore. As Gavai notes, "You can be a crorepati on paper, but if your wallet's dry by month-end, you have a cash flow issue, not a wealth one." If most of your wealth is locked in property or long-term investments, it

cannot be used quickly to handle emergencies or sudden expenses.

### WHY THIS HAPPENS

Many people tend to take on large home loans, invest heavily in real estate, or increase lifestyle spending as their income grows. As a result, their monthly cash flow becomes very tight. When an unexpected crisis hits, such as a medical emergency, job loss or family issue, they may have no choice but to borrow or liquidate long-term investments at a loss.

### HOW TO FIX IT

Gavai encourages people to do a periodic "liquidity audit" and maintain at least six months of household expenses in fully liquid assets like bank savings or sweep FDs. "It's not just what you own—it's how accessible it is," she says.

She also advises checking capital efficiency. "Owning a second flat worth Rs 50L that gives Rs 10K rent? That's a 0.2% monthly yield. Not great," she stated. Simply put, Gavai believes true financial freedom is not only about building assets, it is about having the liquidity to handle emergencies comfortably and sleep peacefully at night.

## Maruti Suzuki rallies 8%: Why GST relief is driving auto stocks higher

**New Delhi.(Agency)**

Auto sector shares jumped sharply on Monday as Sensex and Nifty started the week with a bang after a brief pause due to Independence Day. Both the indices rallied in early trade on Monday, adding over 1% to their previous close.

Top auto sector stocks rallied, sending the market up. The S&P BSE Sensex was up 1,062.91 points to 81,659.75, while the NSE Nifty 50 jumped 356 points to 24,987.30 as of 9:32 am. At the opening bell, Maruti Suzuki surged the most with a sharp gain of 7.14%, followed by Bajaj Finance up 4.79%, Mahindra & Mahindra adding 3.81%, and Bajaj Finserv climbing 3.48%.

Losses were seen in a few heavyweights. Larsen & Toubro slipped 0.57%, ITC fell 0.43%, HCL Technologies

declined 0.31%, Sun Pharmaceutical Industries dropped 0.20%, and Infosys edged lower by 0.11%. Early trade clearly showed strong buying in auto and financial stocks, while IT and pharma names dragged at the bottom.

Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said, "There are strong tailwinds for the market with potential to take it higher. Declarations by the prime minister on the next major reforms in GST by Diwali, is a big positive. The expectation is that most of the goods and services will be in the 5% and 18% tax slabs." He added that sectors like auto and cement, which are presently in the 28% tax slabs are expected to benefit.

### WHY ARE AUTO STOCKS RISING?

Experts suggest that proposed GST changes are expected to bring relief to auto sector companies. "It is a big booster for the auto industry. Auto industry faces one of the highest amounts of tax, especially OEMs like Maruti. So, Maruti even stock like Hyundai Motors is up today in the market. Any reduction of rate cuts for the auto industry is going to be a very big positive factor. M&M also up today. So, it is going to be a positive one for these companies," said Kranthi Bathini, Equity Strategist at WealthMills Securities Pvt Ltd. "TVS Motors, Hero, Eicher, M&M and Maruti are likely to respond positively to the news. Insurance companies are also expected to benefit from the GST revision.

## CIL pushes coal transportation expansion amid Q1 FY26 slowdown in coal demand

**Coal India has scaled up its renewable energy initiatives too, commissioning 114 MW of solar capacity in FY25 and taking its cumulative installed solar capacity to 209.08 MW as of March 2025.**

**Kolkata.(Agency)**

Coal India Ltd (CIL) is pressing ahead with its production and evacuation infrastructure plans under its capital expenditure programme for the current fiscal, even as coal demand remained sluggish in the first quarter of FY 2025-26. The company has earmarked the largest share of Rs 5,622 crore—about 35 per cent of the total proposed Rs 16,000 crore capex in FY26—for coal transportation and evacuation infrastructure, including rail sidings, corridors, coal handling plants, silos and roads. The investments are critical



to ramp up mechanised coal evacuation capacity from the present 151 million tonnes per annum (MTPA) to 994 MTPA by FY 2028-29 under first mile connectivity, an official told PTI. The state-run miner, which accounts for

over 75 per cent of domestic coal output, reported a decline in performance in the June quarter, with production falling 3 per cent to 183.32 million tonnes and offtake slipping 4 per cent to 191 million tonnes. Already,

there are signs of demand improvement after Coal India carried out various reforms for coal consumers, the official said. Despite this, CIL said it remains committed to its long-term roadmap of achieving 1 billion tonnes of production by FY 2028-29. "The Indian growth story remains intact and we are positioning ourselves for future energy requirements," the official said. In addition to evacuation infrastructure, the miner continues to invest in land acquisition, heavy earth moving equipment, washeries and renewable projects, aiming to ensure supply reliability while gradually diversifying its portfolio. Meanwhile, CIL has scaled up its renewable energy initiatives, commissioning 114 MW of solar capacity in FY 2024-25. This took its cumulative installed solar capacity to 209.08 MW as of March 2025, as the miner intensifies efforts to achieve 3 GW of solar capacity by FY 2027-28 under its de-carbonisation roadmap.



# All about Manisha case: Protests in Haryana as teacher, 19, found with slit throat

Forcing teachers to clap at PM's rally is insulting, says AAP



Rajya Sabha MP Sanjay Singh also said that sanitation workers and teachers were being summoned to fill BJP rallies.

**Agency New Delhi.** The Aam Aadmi Party (AAP) on Sunday alleged that Delhi government school teachers were being forced to attend PM Narendra Modi's event merely to clap. AAP leader Manish Sisodia said, "The BJP is unable to find people who willingly attend their programmes. So, a diktat has been issued that every principal and teacher must be present to applaud when the Prime Minister cuts the ribbon. This is deeply shameful." Citing the reverence accorded to teachers in Indian tradition, Sisodia said the BJP must apologise for this "insult." On X, he wrote that teachers, once sent abroad for training under AAP's government, were now reduced to "mere clappers." Rajya Sabha MP Sanjay Singh added that sanitation workers and teachers were being summoned to fill BJP rallies. "They may create fake crowds, but this will bring them no benefit," he further said.

## Army Jawan On Way To Srinagar Pinned To Pole, Assaulted By Toll Booth Staff

**Agency New Delhi.** An Army jawan was pinned to a pole and thrashed during an altercation at a toll booth in Uttar Pradesh's Meerut. Four toll booth staff have been arrested after a video of them assaulting the soldier circulated online. The soldier, Kapil Kavad, is with the Rajput Regiment of the Indian Army. He was home for a holiday and was heading to Delhi airport to fly to his post in Srinagar. Kapil and his cousin got stuck at the crowded Bhuni toll booth. Anxious about getting late for his flight, Kapil got out of the car and started speaking to the toll booth staff. An altercation followed and at least five toll booth employees thrashed Kapil and his cousin. A video of the assault showed them beating Kapil with a stick. Some assailants then pin Kapil to a pole, pull his hands back as one of them hurls abuses and beats up the soldier. Rakesh Kumar Mishra, Superintendent of Police (Rural), said a case has been registered. "Kapil is in the Indian Army. He was returning to his post. There was a long queue at the Bhuni toll booth. He was in a hurry and he spoke to the toll booth staff. An argument began and the toll booth staff assaulted him. Following a complaint from his family, a case was registered at Sarurpur police station." "Four accused have been arrested after scanning CCTV footage and videos. Two more teams are working to arrest the other accused," the senior officer said. According to some reports, the altercation began when Kapil told the toll booth staff that his village is in the area exempted from toll charges. This led to an argument that snowballed into the soldier's assault.

Public anger continues to swell in Bhiwani's Singhani village after the brutal killing of Manisha, a 19-year-old playschool teacher. After protests on Sunday, a mahapanchayat was held on Monday. At the meeting, former BJP minister JP Dalal assured the victim's family of justice, but the gathering insisted that the killers must be arrested first. Markets remained shut over the weekend as locals accused the police of dragging their feet in the investigation. Manisha's body was found on August 13 in a field in Singhani, with her throat slit. While Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has ordered the transfer of the Bhiwani SP and the suspension of five policemen over the handling of the case, opposition leaders allege that the measures are inadequate. Manisha left her school on August 11 to visit a nearby nursing college to enquire about a course but didn't return home. As she didn't return by evening and calls to her phone went unanswered, her father filed a missing person complaint. The Loharu police allegedly dismissed his plea first, suggesting that she had "run away" and "would return in two days", an initial response that was criticised by her parents for its negligence.

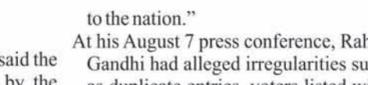
## WHAT IS THE MANISHA MURDER CASE OF HARYANA?

Manisha's family said the police had accompanied them to the nursing college to make enquiries, where three intoxicated men were questioned. The men claimed they had not seen Manisha and added that the college had shut at 1 pm, according to a report by The Indian Express. On August 13, a farmer discovered the body of a young woman in a field near a canal in Singhani village. When police arrived at the spot, they identified the deceased as Manisha, the report added. Following this, the first autopsy was conducted, but her family refused to accept the body, demanding that those significant, which prompted the police to deploy additional personnel to maintain law and order. Refusing to hold her funeral, Manisha's family alleged that police delayed registering their complaint.

When police arrived at the spot, they identified the deceased as Manisha, the report added. Following this, the first autopsy was conducted, but her family refused to accept the body, demanding that those significant, which prompted the police to deploy additional personnel to maintain law and order. Refusing to hold her funeral, Manisha's family alleged that police delayed registering their complaint.

## PEOPLE PROTESTS AS MANISHA CASE REMAINS UNSOLVED

The outrage spilt onto the streets over the weekend. On Saturday, a mahapanchayat near Dhigawa Mandi demanded the immediate arrest of the culprits. Following this, the first autopsy was conducted, but her family refused to accept the body, demanding that those behind the heinous crime be arrested first. The tension at Bhiwani Civil Hospital, where the autopsy was conducted, was



behind the heinous crime be arrested first. The tension at Bhiwani Civil Hospital, where the autopsy was conducted, was

## Over 12K tonnes of waste cleared daily: MCD

**Agency New Delhi.** The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has claimed significant progress under its flagship campaign "Delhi's Freedom From Garbage", held from August 1 to 14. Officials said the fortnight-long drive has mobilised lakhs of citizens and achieved record milestones in cleanliness and waste management across the capital. According to the civic body, 2,61,059 citizens took the swachhta pledge, committing themselves to responsible waste disposal. Thousands also joined awareness activities, rallies, and plogging runs, reflecting collective responsibility for a cleaner capital. Sharing data, officials said 917 office drives were carried out to remove accumulated waste, collecting 10,692 kg of discarded items. In addition, 1,138 cleanliness drives in public toilets were conducted for better hygiene, while 404 night-sweeping operations improved sanitation in commercial areas. Back lanes in congested colonies were targeted through 484 dedicated cleaning drives. To improve public spaces, the civic body said 702 drives were conducted in parks and gardens, 166 in slum clusters, and 1,343 in schools, engaging both staff and students in Swachhta activities. MCD also reported lifting 689.63 metric tonnes of municipal solid waste (MSW) along railway tracks, and collecting a daily average of 12,373 tonnes of waste this month — an increase of more than 1,000 tonnes compared to July's average of 11,000 tonnes. "This marks a significant boost in waste clearance efficiency," an official said. As part of efforts to improve aesthetics, officials said 35,192 posters and banners were removed from public spaces, while 160 wall beautification projects were completed, including murals with cleanliness messages. In slum areas, 205 garbage-vulnerable points were restored, and 417 drains were desilted to prevent waterlogging.

## In name of security is social fabric beginning to fray?

**Agency New Delhi.** Last week a very unfortunate incident took place in Noida when an Indian citizen was labelled a foreigner and denied accommodation in a hotel on account of 'safety measures' ahead of the Independence Day celebrations. According to newspaper reports, a Kolkata-based software engineer and his son, a national level skater, were denied accommodation in Noida on the account of being a Bengali. They were told by the person at the reception that there were police instructions against guests from Bangladesh, Punjab, and Jammu & Kashmir. The police has subsequently denied passing such 'extreme' instructions and come up with details of the notifications as a clarification. However, someone should ask the police, was there a proper briefing of even the beat constables responsible for maintaining law and order at the grassroots about how to implement the detailed instructions of 'keeping the city safe' ahead of the Independence Day celebrations. The capital and its neighbouring districts are turned into a virtual cage ahead of the I-Day and Republic Day celebrations. Roadblocks, ID checks, and heightened police presence are common place during these times. While safety concerns are valid in an era of increased security threats, excessive or ill implemented measures risk turning the region into a "police state" both in appearance and spirit. Unwise implementations, such as targeting people based on their language or region, not only erode civil liberties but also undermine the very security they aim to ensure. For such alienated citizens cooperating with authorities is least in their thoughts, which could be detrimental in times of genuine crisis. No wonder given such draconian instructions under implementation several thousand residents of the Delhi and national capital region make a beeline to neighbouring tourist destinations. One realises that movement within NCR during these two celebrations is not easy. On a more serious note, can those ruling the country allow the capital and its neighbouring districts turn, as mentioned earlier, into a police state not just in word but in spirit too? The incidents like one took place in Noida tears into the cultural and language diversity of our nation.

# Opposition may seek impeachment of poll body chief over 'vote chori': Sources

Meanwhile, CEC Gyanesh Kumar on Sunday strongly countered allegations of electoral fraud levelled by the Congress and its leader Rahul Gandhi, defending the integrity of India's voting process.

**Agency New Delhi.** The Opposition is considering moving an impeachment notice against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar over alleged 'vote chori', sources said. Congress MP Imran Pratapgarhi remarked, "We will be taking a decision very soon." However, ousting the CEC requires a two-thirds majority in both Houses of Parliament - a number the Opposition currently lacks. Meanwhile, CEC Gyanesh Kumar on Sunday strongly countered allegations of electoral fraud levelled by the Congress and its leader Rahul Gandhi, defending the integrity of India's voting process. Without naming Gandhi, Kumar said the "PPT presentation" presented by the

Congress MP offered a "wrong analysis" of voter data, and challenged the Leader of Opposition to either submit an affidavit supporting his claims within seven days or "apologise to the nation." At his August 7 press conference, Rahul Gandhi had alleged irregularities such as duplicate entries, voters listed with



house number zero, and dozens of voters registered to the same address. Kumar dismissed these claims as misrepresentations, citing examples from the Mahadevpura assembly segment in Karnataka's Bangalore Central constituency, where the Congress had in fact won the 2023 state polls. He also clarified that no complaints would be accepted on the draft list of the Special Intensive Revision (SIR) in Bihar after September 1. Addressing specific charges, the Election Commission said allegations of duplicate voting had been mischaracterised. "It is one thing to have a voter's name in more than one booth, and quite another to actually cast votes at two places," Kumar explained, stressing that voting twice is a criminal offence.

# Delhi Airport Joins Global 100-Million Club, Among Top 6 Airports Worldwide

**Agency New Delhi.** Delhi's Indra Gandhi International Airport (IGIA) has joined the elite 100-million-plus club of global airports, with an annual passenger-handling capacity of 109 million. According to data from Official Airline Guide and airport operators, only six airports worldwide belong to this exclusive group. After Terminal 1 was fully operationalised, the milestone was reached in May 2023, and the airport closed in 2024 with the increased capacity. Other than Tokyo Haneda, it is the only airport in Asia to be included in this category. It is run by Delhi International Airport Limited (DIAL). In order to further expand Delhi Airport's overall capacity, plans are also being considered to rebuild



and modernise Terminal 2. According to an official report released last month, the Indian aviation industry has undergone a significant transformation over the past 11 years, fueled by the effectiveness of a comprehensive and integrated approach under significant national

initiatives like PM GatiShakti, the National Logistics Policy, Bharatmala, Sagarmala, and UDAN. India now has 162 airports in operation, including heliports and water aerodromes, up from 74 in 2014, the report stated. As per the official data presented to Parliament, Indian airports handled 412 million passengers in 2024-2025, including 77 million foreign and 335 million domestic travellers. This represents a 9 per cent increase from the previous year. In order to improve regional air connectivity and lower the cost of air travel for the general public, the Regional Connectivity Scheme-Ude Desh ka Aam Nagrik (RCS-UDAN) was introduced in 2016.

# BJP bets on CP Radhakrishnan for Veep post, eyes gains in Tamil Nadu and beyond

The nomination puts the ruling DMK in a spot, forcing it to choose between backing a candidate from its own state or standing firmly with the INDIA bloc.

**Agency New Delhi.** By fielding CP Radhakrishnan as its Vice-Presidential candidate, the Bharatiya Janata Party (BJP) is seeking to strike multiple political chords at once - from caste equations to regional ambitions in Tamil Nadu, while also attempting to unsettle the Opposition. The nomination puts the ruling DMK in a spot, forcing it to choose between backing a candidate from its own state or standing firmly with the INDIA bloc. With 32 MPs across both Houses, the DMK's decision could prove crucial, especially with Tamil Nadu headed for Assembly elections next year. The BJP and AIADMK are likely to seize on the issue if the DMK refuses to lend support. This is not the first time presidential or vice-presidential nominations have tested opposition unity. The Shiv Sena

had broken ranks with the NDA to back UPA candidates Pratibha Patil and Pranab Mukherjee. JD(U) supported Ram Nath Kovind despite being in Opposition at the time. And when Jagdeep Dhankhar was fielded by the NDA for Vice-President, the Trinamool Congress abstained, paving the way for his emphatic victory with 528 votes. This time, the NDA commands 422 votes, but support from parties like the BJD, YSRCP and BRS, which together have 22 MPs, could boost the tally further. For the BJP, the choice of Radhakrishnan carries symbolic and strategic weight. A lifelong party worker with roots in the Rashtriya Swayamsevak Sangh, he embodies the Sangh's ideological grounding and the

BJP's preference for elevating committed organisational leaders to high constitutional posts. Belonging to the OBC community, his candidacy strengthens the party's caste calculus while also bolstering its long-term push in the South. Born in Tiruppur on October 20, 1957, Radhakrishnan has more than four decades of political and public life



behind him. He entered politics as a member of the Bharatiya Jan Sangh's state executive in 1974 and went on to serve as BJP's Tamil Nadu secretary in 1996. Twice elected as Lok Sabha MP from Coimbatore in 1998 and 1999, he chaired the Parliamentary Standing Committee on Textiles and contributed to committees on Finance and Public Sector Undertakings. Radhakrishnan's career has also taken him to international platforms - from representing India at the UN General Assembly in 2004 to being part of the country's first parliamentary delegation to Taiwan. As BJP's Tamil Nadu president between 2004 and 2007, he spearheaded a 93-day, 19,000-km rath yatra.

## NEWS BOX

## New wave of genocide and displacement: Hamas rejects Israel's Gaza relocation plan

World. (Agency)

Palestinian militant group Hamas said on Sunday that Israel's plan to relocate residents from Gaza City constitutes a "new wave of genocide and displacement" for hundreds of thousands of residents in the area. The group said the planned deployment of tents and other shelter equipment by Israel into southern Gaza was a "blatant deception".

The Israeli military has said it is preparing to provide tents and other equipment starting from Sunday ahead of its plan to relocate residents from combat zones to the south of the enclave "to ensure their safety".

Hamas said in a statement that the deployment of tents under the guise of humanitarian purposes is a blatant deception intended to "cover up a brutal crime that the occupation forces prepare to execute". Israel said earlier this month that it intended to launch a new offensive to seize control of northern Gaza City, the enclave's largest urban centre. The plan has raised international alarm over the fate of the demolished strip, which is home to about 2.2 million people.

The war began when Hamas attacked southern Israel on October 7, 2023, killing 1,200 people and taking 251 hostages, according to Israeli authorities. About 20 of the remaining 50 hostages in Gaza are believed to be still alive.

Israel's subsequent military assault against Hamas has killed over 61,000 Palestinians, Gaza's health ministry says. It has also caused a hunger crisis, internally displaced most of Gaza's population and left much of the enclave in ruins.

## 11 injured as Russia strikes Kharkiv with ballistic missile

World. (Agency)

Russia hit a residential area in Kharkiv with a ballistic missile, injuring at least 11 people, Ukrainian authorities said late on Sunday, as the US president presses Kyiv to accept a quick deal to end the war that Moscow had started. Among the injured in Kharkiv, Ukraine's second-largest city, was a 13-year-old girl, Oleh Synchubov, governor of the broader Kharkiv region said on the Telegram messaging app.

Kharkiv, which lies in northeastern Ukraine near the border with Russia, has been the target of regular Russian drone and missile attacks since the start of the war that Moscow launched with a full-scale invasion in February 2022. "The blast wave shattered windows in nearby apartment buildings," Ukraine's State Emergency Service said on Telegram. It added that some residents had to be evacuated.

Reuters' witnesses saw medics attending to residents on a street and rescuers inspecting damage in residential buildings.

A 57-year-old woman was injured in Russia's guided aerial bomb strike on the northeastern region of Sumy that also damaged at least a dozen residential houses and an educational institution building, regional authorities said. "The enemy continues to deliberately target civilian infrastructure in the Sumy region — treacherously, at night," Oleh Hryhorov, head of the regional administration in Sumy, said on Telegram.

Reuters could not independently verify what weapons Russia used. There was no immediate comment from Moscow. Both sides deny targeting civilians in their strikes, but thousands of people have died, the vast majority of them Ukrainian. President Donald Trump, who hosted President Vladimir Putin in Alaska on Friday for bilateral talks aimed at ending the war, has urged Kyiv to make a deal with Moscow, stating, "Russia is a very big power, and they're not."

## Trump's DC crackdown sees 68 arrests overnight, Democrats call it a stunt

World. (Agency)

Attorney General Pam Bondi announced on Sunday that federal and DC law enforcement authorities arrested 68 people overnight in Washington DC, as part of a federal crackdown on crime ordered by President Trump. "Over 300 arrests in DC — and counting: Just last night, our federal and DC law enforcement partners made 68 arrests and seized 15 illegal firearms," Bondi said in a post on X. "Homicide suspects, drug traffickers, and more are being charged. I'll continue to stand with you as we make DC safe again!"

Trump announced last week that he would federalise the city's police force and deploy the National Guard. The decision sparked backlash from Democrats and DC residents who accused the administration of overreach.

A White House official told NewsNation that Saturday night's operations involved 1,800 participants and emphasised that the National Guard was "not making arrests at this time."

## REPUBLICANS DEFEND CRACKDOWN AS DEMOCRATS CALL IT A STUNT

White House deputy chief of staff Stephen Miller defended the president's actions, writing on X that "graffiti is coming down in Washington, DC" He added, "Grafitti left untouched to scar public spaces is the visual declaration of a society's surrender." "What's happening here in Washington DC, is just a stunt," Senator Chris Murphy said on Meet the Press. Murphy suggested the move was designed to distract from other controversies, including questions over unreleased Epstein files and rising healthcare costs.

"He didn't want to talk anymore about the fact that our healthcare system is about to collapse because of the cuts that they have made, that premiums are going to go up by 75 percent on Americans," Murphy added. Republicans, meanwhile, argue the operation is necessary given violent crime in the capital and claim Democrats have failed to manage the issue effectively.

## Spare China but hit India: US Secretary of State defends Russian oil hypocrisy

Speaking to Fox News

on August 17, Marco

Rubio cautioned that

targeting Chinese

refiners would have

disruptive consequences

for the global oil market.

World. (Agency)

US Secretary of State Marco Rubio has acknowledged that imposing secondary sanctions on China for refining Russian oil could drive up global energy prices, even as Washington has punished India with additional tariffs for continuing to purchase crude from Moscow.

Speaking to Fox News on August 17, Rubio cautioned that targeting Chinese refiners would have disruptive consequences for the global oil market. "If you impose secondary sanctions on a country, as in the

case of Russian oil shipments to China, China will simply refine that oil and it will return to the global market. Anyone buying this oil will pay a higher price, or if it is unavailable, they will have to look for alternative sources," he said.

Rubio revealed that European nations have already expressed unease over such measures. "When we discussed the Senate bill proposing a 100 percent tariff on China and India, we heard from a number of European countries that they were unhappy with that possibility," he added. His comments came after he had earlier stressed that India's energy trade with Moscow has long been a sore spot in Washington. Speaking to Fox Radio, Rubio said India's continued purchases of Russian oil were "helping to sustain the Russian war effort in Ukraine" and were "most certainly a point of irritation" in New Delhi's relationship with

the United States, though not the only one. "India has huge energy needs and that includes the ability to buy oil and coal and gas and things that it needs to power its economy like every country does, and it

sustains the Russian war effort. So it is most certainly a point of irritation in our relationship with India - not the only point of irritation. We also have many other points of cooperation with them.

"Yet, while the US has refrained from sanctioning China, Washington has moved aggressively against India. After first imposing a 25 percent tariff on Indian goods, President Donald Trump recently doubled the duty to 50 percent, penalising New Delhi for persisting with Russian oil imports.

The White House also warned India that secondary sanctions could follow if it did not alter its course.

The move has sparked accusations of double standards, with critics pointing out that China continues to import large volumes of Russian oil without facing similar punitive measures. Despite Trump's repeated threats, India has maintained there has been no pause in its Russian oil purchases and accused Washington of hypocrisy.



## Spain deploys 500 more soldiers as wildfires rage; Europe sends reinforcements

World. (Agency)

Spain is deploying a further 500 soldiers to battle wildfires that have torn through parched woodland during a prolonged spell of scorching weather,

Prime Minister Pedro Sanchez said Sunday. The decision to add to the more than 1,400 troops already on wildfire duty came as authorities struggled to contain forest blazes, especially in the northwestern Galicia region, and awaited the arrival of promised aircraft reinforcements from other European countries. Firefighters are tackling 12 major wildfires in Galicia, all of them near the city of Ourense, the head of the Galician regional government Alfonso Rueda told a press conference with Sanchez.

"Homes are still under threat so we have lockdowns in place and are carrying out evacuations," Rueda said. Galicia has been battling the spreading flames for more than a week. Temperatures in

Spain could reach 45 Celsius (113 Fahrenheit) in some areas Sunday, the Spanish national weather agency AEMET said. On Saturday, the maximum temperature was 44.7 C



(112.46 F) in the southern city of Cordoba, it said.

"This Sunday, when extraordinarily high temperatures are expected, the danger of wildfires is extreme in most of the country," AEMET said on the social platform X. The fires in Spain this year

have burned 158,000 hectares (390,000 acres), according to the European Union's European Forest Fire Information System. That is an area roughly as big as metropolitan London.

Europe has been warming twice as fast as the global average since the 1980s, according to the EU's Copernicus Climate Change Service. Scientists say that climate change is exacerbating the frequency and intensity of heat and dryness in parts of Europe, making the region more vulnerable to wildfires.

## SPAIN AWAITING EUROPEAN FIREFIGHTERS, MORE PLANES

Spain was expecting the arrival of two Dutch water-dumping planes that were to join aircraft from France and Italy already helping Spanish authorities under a European cooperation agreement.

## 3 dead after semi-truck driver takes illegal U-turn on Florida turnpike

World. (Agency)

A semi-truck driver has been arrested for vehicular homicide after an illegal U-turn on the Florida Turnpike led to a crash that killed three people. Authorities identified the driver as Harjinder Singh, who has been living in the US illegally since 2018. "These are the alleged semi-truck drivers who killed three people while making a U-turn at an 'Official Use Only' turn on the Florida Turnpike. The Florida Highway Patrol is describing the wreck as a homicide investigation," one individual wrote while sharing video of the crash.

The video, filmed from inside the semi-truck's cab, shows the moment Singh makes the sudden U-turn, triggering a deadly collision with an oncoming vehicle.

## OFFICIALS CALL CRASH



## "SHOCKING AND CRIMINAL"

A statement from the Official White House Rapid Response confirmed Singh's arrest, saying he faces both state and federal charges. "This individual is an illegal immigrant who was granted a commercial driver's license by the State of California — and now, three innocent people are dead. He has been arrested for

vehicular homicide and an ICE detainer has been issued."

Florida Highway Patrol Executive Director Dave Kerner condemned Singh's actions. "The actions taken by the Defendant while operating a commercial tractor-trailer are both shocking and criminal," Kerner said.

"Three people lost their lives as a result of his recklessness, and countless friends and family members will experience the pain of their loss forever. Harjinder Singh is in custody on state vehicular homicide charges and immigration violations. He will no longer be able to damage and destroy the lives of Floridians and visitors. At the conclusion of his state charges, he will be deported. The Florida Highway Patrol remains committed to enforcing both state and federal law to ensure that people that are a danger to others face justice behind bars."

## 'Forget Nato, Crimea': Is Trump throwing Zelenskyy under the bus for Russia deal?

World. (Agency)

Ahead of his meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and European leaders at the White House, US President Donald Trump on Monday ruled out the possibility of Kyiv reclaiming Crimea from Moscow and urged his counterpart not to pursue Nato membership — a key sticking point with Russia.

Surprisingly, Trump's remarks came even after his special envoy, Steve Witkoff, told CNN that Moscow was willing to let the US and its European allies provide Nato-style security guarantees to Kyiv as part of a potential peace deal, describing the development as "game-changing." Meanwhile, Putin has made no such commitment publicly. The Russian leader has consistently opposed Nato's post-Cold War expansion into Eastern Europe, much of which once lay within the Soviet sphere.

When Poland, Hungary, and the Czech

Republic joined Nato more than two decades ago, Putin voiced his concerns openly. With Ukraine far closer both geographically and culturally, the Kremlin has drawn an even harder line against any Nato presence on its doorstep.

But Witkoff, following Trump's meeting with Putin, claimed that the Russian President had agreed to let the US or Europe provide a Nato-like security cover to Ukraine. "We were able to win the following concession: That the United States could offer Article 5-like protection, which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in NATO," Trump's main negotiator, Steve Witkoff, who held hectic parleys in Moscow ahead of the recently concluded Alaska meeting with Vladimir Putin, told CNN.

Calling it a major breakthrough, Witkoff added that this was the first time Moscow had agreed to such a proposal. Article 5 of the North Atlantic Treaty, also known as



the Washington Treaty, is the basis of Nato's principle of collective defence. It states that an armed attack against any of the alliance's 32 members in Europe or North America shall be considered an attack against them all.

However, Witkoff's assertions came crashing down when Trump ruled out Nato-style protection for Ukraine, even as European leaders flocked to the White House with Zelenskyy. Trump further

suggested that the decision to end the conflict lies with Zelenskyy, remarking that he "can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight." Blaming former US President Barack Obama for allowing Russia's annexation of Crimea "without a shot being fired" in 2014, Trump reiterated his stance on Truth Social, saying, "President Zelenskyy of Ukraine can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight. Remember how it started. No getting back Obama given Crimea (12 years ago, without a shot being fired!), and NO GOING INTO NATO BY UKRAINE. Some things never change!!!"

Even though the idea of Trump asking Zelenskyy to hand over Ukraine's Donbas to Russia for a peace deal sounded suicidal—since it would open up the country's eastern front to Russia—the US President's latest remarks will come as a double blow.

## Thousands of Israelis protest to demand release of hostages, end to Gaza war

World. (Agency)



Thousands of Israelis took part in a nationwide strike on Sunday to show solidarity with the families of hostages held in Gaza, urging Prime Minister Benjamin Netanyahu to reach an agreement with Hamas to end the war and secure the captives' release.

Protesters waved Israeli flags and carried photos of hostages, while whistles, horns, and drums rang out at rallies across the country. Some protesters blocked major roads, including the key route between Jerusalem and Tel Aviv. "Today, everything stops to honor the highest value: the sanctity of life," said Anat Angrest, whose son Matan is among those held, speaking at a public square in Tel Aviv. Israeli actress Gal Gadot, famous for her roles in Wonder Woman and the Fast & Furious franchise, also met with families of hostages during the demonstrations.

The strike, organised by the hostages' families, saw mixed participation from businesses, with some allowing staff to join while others remained open. Schools were unaffected due to the summer break. By early afternoon, police reported detaining 38 demonstrators after some clashes over blocked roads. Demonstrations were temporarily paused around 4 pm local time when air raid sirens warned of a missile fired from Yemen, which was successfully intercepted. In a cabinet meeting, Netanyahu stated that calls to end the war without defeating Hamas only strengthen the group and delay hostage releases. The prime minister, heading Israel's most right-wing government, reaffirmed plans for the military to seize Gaza City, one of the few areas not under Israeli control.

Many Israelis, particularly hostages' families, oppose the move, fearing it could endanger captives still alive. Israeli officials estimate that around 20 of the 50 remaining hostages in Gaza are alive.

Opposition leader Yair Lapid attended a rally in Tel Aviv, praising the demonstrators' solidarity. "The only thing that strengthens the country is the wonderful spirit of people stepping out today," he wrote on X. Since the Hamas attack on Israel in October 2023, the conflict has left thousands dead on both sides. According to Gaza health officials, over 61,000 Palestinians have died due to Israel's military operations, including at least 29 on Sunday.

## NEWS BOX

**PKL: Haryana Steelers announce Jaideep Dahiya as captain ahead of season 12****New Delhi. (Agency)**

Defending Pro Kabaddi League champions Haryana Steelers have announced Jaideep Dahiya as their captain ahead of the start of season 12 of the tournament. Rahul Sethpal will serve as the vice-captain of the team as the Steelers aim to be only the second team to defend their PKL crown.

Dahiya has been an integral part of Steelers over the past few seasons and has 231 raid points and 227 tackle points in the 87 matches he has played in PKL so far. Like Dahiya, Sethpal played a big role in the Steelers winning the title last season, as he got 73 tackle points from 24 matches in 2024. Speaking about the announcement, Steelers coach Manpreet Singh said that both Dahiya and Sethpal bring in unity and quick decision-making to the mat. Singh also said that the duo have been role models for the team on and off the mat and have set a benchmark for the whole squad.

The Steelers coach also said that he is confident that side will be able to lift the trophy once again.

"Kabaddi is a game that demands unity and quick decision-making, and both Jaideep and Rahul bring those qualities to the mat. Both have been essential to our success last season, on and off the mat.

Their discipline, consistency and exceptional performances inspired the squad and set the benchmark on how we want to tackle this season. With new vigour and focus, the Dhaakad Boys are back this season - we are confident to defend our title and lifting the trophy again," said Singh.

While the Steelers are without their star all-rounder Mohammadreza Shadloui for this season, they got Naveen Kumar during the auction. The defending champions will start their campaign on August 31 against the Bengal Warriorz.

**Cincinnati Open: Iga Swiatek downs Elena Rybakina, faces Jasmine Paolini in final****New Delhi. (Agency)**

World No. 3 Iga Swiatek produced a clinical performance on Sunday to defeat Elena Rybakina 7-5, 6-3 and book her first-ever Cincinnati Open final, continuing her dominant run at the U.S. Open warm-up tournament.

Having fallen in the semi-finals in both 2022 and 2023, Swiatek was determined not to let history repeat itself. Despite a rocky start against the powerful Rybakina, the four-time Grand Slam champion shifted gears midway through the opening set, winning 10 of the final 13 games to close out the match in just under 100 minutes.

"That was a tough match. At the beginning, the level was pretty crazy," Swiatek said in her post-match interview. "We played so fast that sometimes we couldn't even run to the second ball. But I was there to play with intensity and good quality, and I am super happy with the performance."

Rybakina, the ninth seed, looked in control early, breaking Swiatek with a blistering cross-court forehand to go up 5-3. But the Polish star, laser-focused under pressure, reeled off four straight games to steal the set 7-5. She continued to dictate in the second, breaking early and fending off a late Rybakina surge before sealing the win when the Kazakh sent a forehand return long.

Swiatek has yet to drop a set in Cincinnati and will look to carry that form into the final, where she'll meet Italian seventh seed Jasmine Paolini.

Paolini survived a tough three-set battle against unseeded Veronika Kudermetova, eventually prevailing 6-3, 6-7(2), 6-3 to reach her second WTA 1000 final of the year. After surrendering a 5-3 lead in the second set and losing the tiebreak, Paolini regrouped impressively to take control of the decider.

"I said to myself after losing the tiebreak that I have to step back on court, be in the present and don't think about what happened," Paolini reflected. "You have to keep going, and that was the key to forget and go back and fight." Sunday's final will be the sixth meeting between Swiatek and Paolini, with the Polish star leading their head-to-head 5-0. Their most recent clash came just two months ago at the Bad Homburg Open, where Swiatek won in straight sets.

**Jannik Sinner, Carlos Alcaraz brace for yet another final before US Open festival**

**Jannik Sinner and Carlos Alcaraz are set for another blockbuster final at the Cincinnati Open, their fourth title clash of 2025 and 14th meeting overall. With Alcaraz leading the rivalry 8-5 but Sinner riding the high of his historic Wimbledon triumph, Monday's showdown promises to be a gripping prelude to the US Open.**

**New Delhi. (Agency)**

Get ready for an electrifying showdown! On Monday, the Cincinnati Open final will bring us the highly anticipated fifth clash between Jannik Sinner and Carlos Alcaraz—and it's set to be a spectacle! This marks their fourth final encounter of 2025, and with each match they've played, their rivalry has only grown more intense and gripping. The Italian Open, French Open, Wimbledon, and now the Cincinnati Masters have all played host to

these titanic battles, and Monday promises to deliver even more.

Of their three encounters this year, Alcaraz has the edge with two wins, including his commanding victories at the French Open and Rome. But Sinner shocked the tennis world at Wimbledon, powering past Alcaraz in four sets to secure his first-ever Grand Slam at the All England Club—a moment that added an unexpected twist to their already fierce rivalry.

Currently, Alcaraz leads their head-to-head 8-5, but Sinner's breakthrough win at Wimbledon has certainly shifted the dynamic, with a renewed sense of possibility for the Italian. As of now, Alcaraz is ranked No. 2 in the world, while Sinner is in the top spot, marking an incredible leap for both players over the past year.

With their contrasting styles—Sinner's relentless baseline power and Alcaraz's thrilling all-court flair—each of their matchups has been a fireworks display of athleticism, and Monday's final is shaping up to be no different. Both players are hungry for a major title just days before the US



Open, and you won't want to miss a single moment of this epic clash!

**Can Sinner carry the momentum from Wimbledon?**

Alcaraz had been on a remarkable tear against Sinner, riding a five-match win streak, which included the unforgettable 2025 French Open final. There, he pulled off a jaw-dropping comeback from two sets down—saving three championship points along the way—underscoring his mental toughness and dominance in high-stakes moments. That streak was a testament to Alcaraz's ability to rise to the occasion when it mattered most, especially in their most

pressure-packed encounters.

But Sinner has been an absolute force on hard courts. After back-to-back Australian Open titles in 2024 and 2025, and his triumph at the 2024 US Open, he became just the fourth man to win three straight hard-court Grand Slams—joining the ranks of legends like Djokovic in 2015-16. His mastery of the hard-court game is unmatched, and he's proven himself to be the ultimate big-match player on this surface. Then came Wimbledon 2025—a game-changer. Sinner struck back in a massive way, breaking Alcaraz's five-match win streak by coming up trumps at Wimbledon. That moment was more than just a Grand Slam win—it was a statement. A defining shift in their rivalry, showing that Sinner is more than capable of taking down the world No. 2 when the stakes are at their highest.

Now, with both players at the top of their game, Monday's Cincinnati Open final promises to be the latest epic installment in this thrilling saga. Who will claim the next major title before the US Open? The excitement is off the charts!

**Individuals stepped up to win matches: Sundar reflects on India's fight in England****New Delhi. (Agency)**

All-rounder Washington Sundar said the younger Indian side that toured England was full of energy and unity during the recently concluded Anderson-Tendulkar Trophy. He

described the camp atmosphere as "fabulous" and noted that everyone was eager to take responsibility. The 25-year-old, one of India's standout performers in the series, added that the team entered the contest knowing every player needed to step up in tough situations. He felt the players supported one another and built strong bonds both on and off the field.

Reflecting on the series, Sundar said the mood within the youthful squad was very special. "Truly, the way the dressing room environment was built—it was fabulous. It's an amazing atmosphere to be part of, especially because we're all quite young, and that makes it extremely

exciting," he told Wisden.

Sundar impressed with both bat and ball, scoring 284 runs across four matches—including his maiden Test hundred and a half-century. He also claimed



seven wickets, with best figures of four in an innings. In the fifth Test at The Oval, he smashed 53 off just 46 balls, helping India post a competitive total in the third innings. The all-rounder admitted the players were

aware of the challenge ahead and ready to face it. Touring England is never easy, and with stalwarts Virat Kohli, Ravichandran Ashwin, and Rohit Sharma having retired, the task was even tougher for the Shubman Gill-led side.

"Coming into the series, we knew that all of us would need to step up in different situations. And looking back now, that's exactly what happened. So many individuals rose to the occasion and turned key moments into match-winning ones for the team," he added. Throughout the series, the camaraderie within the group was remarkable and likely played a major role in helping India bounce back from a heavy defeat at Headingley and a heartbreaking loss at Lord's. "This is exactly the kind of team we've always wanted to be part of—and we became that in this series. We've built some amazing bonds on and off the field," he concluded.

**After maiden England call-up, Sonny Baker shines with hat-trick in Hundred****New Delhi. (Agency)**

Sonny Baker delivered a dream performance in The Hundred, taking a sensational hat-trick to power Manchester Originals to a commanding 57-run victory over Northern Superchargers on Sunday.

The 21-year-old fast bowler, fresh from his maiden England call-up, became only the fourth bowler in men's Hundred history to achieve the feat, joining Sam Curran, Imran Tahir and Tymal Mills. Baker's magic arrived in his third set of deliveries at the death. He first removed the experienced Dawid Malan before crashing through the stumps of Tom Lawes and Jacob Duffy with successive balls. The Superchargers, already reeling in their chase, were skittled for just 114. Baker finished with superb figures of 3 for 21, capping off a dominant outing for the Originals.

Earlier, skipper Jos Buttler anchored the

innings with a fluent 64 off 45 balls, while Heinrich Klaasen smashed an unbeaten 50, lifting the team to 171 for three—a total that proved well out of reach once Baker's fiery spell sealed the contest.



**Sonny Baker earns England call-up**

Sonny Baker has capped a remarkable rise with his maiden England senior call-up, named in the squads for both the upcoming ODI series against South Africa and the

T20I series against Ireland. At just 22, the Exeter-born fast bowler has earned a reputation for raw pace—regularly clocking above 90 mph—combined with the rare ability to swing the ball at high speed.

His steady climb through Somerset, the England Under-19s, and the England Lions has now brought him the ultimate reward. Baker's selection comes on the back of eye-catching performances in domestic white-ball cricket.

In the 2025 Vitality Blast, he picked up eight wickets in seven matches at an average of 27.25, with best figures of 3/28. His sensational hat-trick in The Hundred only strengthened the case for his inclusion. Though yet to make his T20I debut, Baker's overall T20 record is already impressive: 22 wickets in 19 matches at an average of 24.81, including best figures of 4/20.

**Watch: Neymar Jr. breaks down in tears after Santos get thrashed 0-6 by Vasco**

**Neymar broke down in tears after Santos' 6-0 loss to Vasco da Gama. The star slammed the team's "terrible attitude" as Santos sacked coach Cleber Xavier.**

**New Delhi. (Agency)**

Neymar Jr. was left in tears following Santos' humiliating loss to Vasco da Gama on Sunday, August 17, as the legendary Brazilian club slipped to a new low. A brace from Philippe Coutinho and goals from Lucas Piton, David Fonseca, Rayan and Danilo Neves were enough for Vasco to secure the win and hand Santos their 10th loss of the season from 19 games. The performance from Santos left their fans fuming, with many opting to leave the stadium while others turned their back on the team. They were seen calling the Santos side 'shameless' and even cheered for Vasco at the end.

This left Neymar emotional as he slumped to the ground and was in tears. Even as he made his way to the tunnel, the Brazilian star was inconsolable and continued to weep. You can see the full video below:



**Neymar slams Santos after heavy loss**

While sharing his thoughts about Sunday's performance, Neymar didn't mince words, slamming the Santos team. The 33-year-old said the attitude of the team was terrible and it was a shame to play in that fashion while wearing the Santos jersey.

"You have to explain our attitude on the field. Which, to sum it all up, was terrible," Neymar told Brazilian media, as quoted by Reuters.

"It's a shame to play like that wearing the Santos jersey. I think everyone today needs to lay their head on their pillow, go home, and think about what they want to do."

"Because with today's attitude, if we have to do what we did today on the field, I don't think we even need to show up on Wednesday." The defeat came with consequences as Santos sacked Cleber Xavier after the loss. Santos currently sits 15th in the Brazilian top flight. "Santos

Futebol Clube announces the departure of coach Cleber Xavier. The club thanks the coach for his services and wishes him luck in his future career," Santos said in a statement posted on social media. Santos face Bahia up next on August 24 in the league.



# Jannat Zubair's

**'Pink Era' Is Too Sexy To Miss: Check Out Her Barbie Glam In Recent Dump**

Jannat Zubair's photo dump never disappoints, and today the actress shared a series of pictures enjoying her pink era, and we can't get enough of her Barbie glam. In the series, Jannat can be seen wearing different shades of pink, giving major fashion inspiration. While the first picture shows her in a chic tank top, it's the second photo in the carousel where she truly channels her inner mermaid. In that picture, Jannat Zubair is serving a dreamy, vacation-perfect look. She stands waist-deep in water against the backdrop of a majestic waterfall, giving the frame a cinematic and refreshing vibe. A faint rainbow near the waterfall adds a magical touch.

Dressed in a strappy, body-hugging pink slip dress with delicate detailing, she looked drop-dead gorgeous. The wet fabric clings to her frame, making the look all the more swoon-worthy. Her pose—one hand resting on her head as she gazes upwards—exudes confidence and poise. With her no-makeup look, glowing skin, and damp hair left open, Jannat had hearts racing. Another picture in the carousel shows her exuding elegance in a soft pink one-shoulder ribbed top featuring a stylish cut-out detail, paired with sleek white high-waist jeans. With dewy makeup, pink lips, and a hint of tint, she accessorised the look with simple gold hoop earrings. In yet another look, Jannat stuns in a satin blush pink top with a



plunging neckline and tie-up sleeves, paired with a denim mini skirt for a laid-back yet stylish appeal. With her hair left open and natural, glowing makeup, the actress radiated main-character energy.

**More about Jannat Zubair**

On the work front, Jannat Zubair recently won hearts with her appearance on the reality show *The Traitors*, hosted by Karan Johar, where she was eliminated by the traitors. She later appeared on *Laughter Chefs* for a few episodes. The actress also made headlines recently after rumours of her breakup with Faisal Shaikh, aka Faisu, caught fire. Jannat and Faisal, who have worked together on several projects, often share photos with each other on social media. While their dating rumours frequently make headlines, the duo has repeatedly denied them, claiming they are just close friends.

**Prajakta Koli Reacts To Her Viral Wedding Video: 'I Couldn't Walk Straight...'**



YouTube sensation and *Mismatched* star Prajakta Koli said "I do" to her boyfriend of 11 years, Vrishank Khanal, on February 25. After the big day, the couple celebrated with a fun-filled party — complete with a viral moment of Prajakta shaking a leg to Sunil Grover's hilarious *Mere Husband Mujhko Piyar Nahin Karte*. Her unconventional choice of song had the internet in splits and fans couldn't get enough of her quirky, cheeky performance. And now, in an exclusive chat with *News18 Showsha* during the promotions of her new show *Andhera*, Prajakta shared behind-the-scenes of the viral video.

**Prajakta Koli Viral Wedding Sangeet Video**

The viral video featured Prajakta performing alongside friends, including comedian Mallika Dua and actor Mithila Palkar. While singing, she looked at Vrishank and mouthed, "Zindagi barbaad ho gaya, inko aata hi nahi hai, inko pata hi nahi hai, romance nahi karte, dance nahi karte, inko patti hi nahi hai!" (My life is ruined; he doesn't know how to do anything, he has no clue, he doesn't do romance, he doesn't dance, he just doesn't care). The performance had the wedding guests in splits, with laughter echoing in the background. Recalling the evening, she said, "I couldn't walk straight! That's how many beverages I had had at that point. And I mean our family and our friends — they were actually lovely. We told them that we don't want to share too much content. Par har family mein woh ek mausi toh hoti hai. Humari waali aayi thi Jaipur se. She shot it and uploaded it. And of all the things that she could have shared, I wouldn't have minded most of it (laughs)! It was actually released after 3-4 days of the wedding. And it kind of did what it did! There is actually no story behind it. It is just mimosas!" Prajakta and Vrishank's wedding was held at a picturesque farm in Karjat, Maharashtra, with close friends and family in attendance. Prajakta Koli rose to fame with her YouTube channel *MostlySane*, which has over 7.23 million subscribers.

**Armaan Malik's First Wife Payal Pregnant With Fourth Child, Not Kritika: 'It's A Miracle'**



For weeks, social media conversations have centered on YouTuber and *Bigg Boss* OTT 3 finalist Armaan Malik and his family. Speculations suggested that his second wife, Kritika, was expecting her second child after she was seen holding a pregnancy test kit in her hands in recent photos. However, it is actually Payal, Armaan's first wife, who is pregnant. This will be Armaan and Payal's fourth child together. Payal, already a mother to three children—Chirayu and twins Ayan and Tuba—recently announced in her latest vlog that she is expecting again. This update came after days of confusion caused by Kritika's post, where she was seen holding a pregnancy kit, leading fans to believe she was the one expecting. Payal's revelation clarified the misunderstanding.

In her viral vlog, Payal discussed her journey with fertility treatments with Armaan. She shared her struggles with failed IVF attempts, which had left her emotionally exhausted. Despite these setbacks, she described her current pregnancy as a miracle, something she never thought possible. Payal recalled that her son Chirayu was born after years of waiting, and later she pursued more children through IVF.

"Miracle hi hai sach mein. 4 saal baad Chiku hua tha kyuki tube nai thi. Phir maine socha bache hone chahiye. Maine joh bacho ka sukha nai dekha woh maine IVF se karwaya. Ek baar IVF fail hoh gayi. Dusri baar miracle tha. Ek tube mei kaise 15 saal baad mei pregnant hui?" she said.

Meanwhile, in another vlog, Armaan Malik said, "Payal ne naturally conceive kiya hai, aur ye ek ajooba hai. Matlab ho hi nahi sakta tha."

**Armaan Malik's Two Marriages**

Armaan Malik married Payal in 2011 and later welcomed a son named Chirayu Malik. Six years later, in 2018, Armaan married Payal's best friend, Kritika, without legally ending his first marriage. They also have a son named Zaid.

The three grabbed everyone's attention after they participated in *Bigg Boss* OTT in 2024. While Payal was the first one to get eliminated, Armaan walked out of the show during the finale week. Kritika was one of the finalists on *Bigg Boss* OTT 3.

# Anusha Dandekar

**Looks Sexy In Lilac Bikini As She Vacations In Mykonos, Greece**

Anusha Dandekar is raising the temperature on Instagram with her latest vacation pictures from Mykonos, Greece. The actress, VJ, and fashion icon shared a series of breathtaking shots in which she is seen soaking up the Mediterranean sun and flaunting her impeccable style. In the first picture, Anusha is captured mid-dive into a sparkling blue pool, sporting a lilac bikini that perfectly complements the scenic backdrop of the Aegean Sea. The second photo shows her striking a



confident pose against the ocean view, exuding glamor and elegance. The third snap, perhaps the most captivating, is a close-up of Anusha lounging effortlessly, letting her natural beauty shine. Her caption, "How deep is your love?" accompanied by a

blue heart, matched the carefree and romantic vibe of the photoshoot. She also credited photographer and close friend Melina Foteinou for capturing the vibrant moments. Anusha Dandekar rose to popularity in the entertainment industry as a VJ. She has hosted several youth shows, such as *MTV Dance Crew*, *MTV Teen Diva*, and *India's Next Top Model*. She was also cast in films including *Delhi Belly*, *Hello*, and *Lalbag Parel*, among others. She will next be seen in the Marathi film *Baap Manus*.

A couple of years ago, Anusha Dandekar shared that she went through surgery to remove a lump from her ovary. During the procedure, physicians discovered that there was more than one lump. She continued, saying that her rehabilitation process had been "pretty intense."

Anusha shared more details on her Instagram post and mentioned that she was, "super lucky everything is great now." The actress also shared advice for all women. She wrote, "Just wanted to tell all the girls that are here reading this, to make sure you visit your gynaecologist once a year without fail to stay ahead of your health and safety, I've been

doing that since I was 17, and that's how I can be so grateful I'm recovering well today." Anusha also expressed her gratitude to the doctor and the hospital staff who treated her.

